सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023
www.newsparivahan.com
परिवहन विशेष
वर्ष 02, अंक 307, नई दिल्ली। बुधवार, 15 जनवरी 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार
अगर फैसले सही लिए हैं तो वक्त जरूर लगेगा पर अच्छे साबित जरूर होंगे।

03 "आपदा से भाजपा ही दिल्ली वासियों को मुक्ति दिला की सकती है"
06 घटते छात्र, बढ़ते स्कूल
08 बासुकिनाथ मंदिर से राजस्थान के जस्टिस की मोबाइल चोरी, बरामद

दिल्ली परिवहन आयुक्त प्रशासनिक अधिकारी है या राजनेता ?

दिल्ली परिवहन आयुक्त ने अपने गैर कानूनी आदेश से उत्पन्न वाहन मालिकों की समस्या के हल की जगह राजनेताओं की तरह दिया लोलीपॉप

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन आयुक्त ने एक निजी कम्पनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बुराड़ी वाहन जांच शाखा से वाहनों की जांच बंद करने की आदेश कर उन्हें झूलझूली वाहन जांच शाखा में जांच कराने के आदेश जारी कर दिए ओर वह भी यह जानते हुए की झूलझूली वाहन जांच शाखा में 250 से अधिक वाहनों की जांच संभव ही नहीं है और दो पारी छोड़ 24 घंटे भी जांच कर देने पर भी लगी हुई ऑटोमेटिक मशीनों से 300 से अधिक वाहनों की जांच संभव नहीं है।

बिना ऑटोमेटिक मशीनों के वाहन जांच के लिए झूलझूली वाहन जांच शाखा क्या या बुराड़ी वाहन जांच शाखा क्या ?

वाहन मालिकों, संस्थाओं, यूनियंस और अन्य सभी व्यवसायियों के विरोध जताने पर **परिवहन आयुक्त ने इस समस्या के लिए हल देने की जगह लोगों को राजनेताओं की तरह लोलीपॉप दे दिया**

परिवहन आयुक्त ने दो श्रेणी (6+1 सवारी) के वाहनों जिसमें कुल पंजीकृत वाहन 1500 ही हैं और दोनों श्रेणियां के वाहन दिल्ली की जनता को एक प्वाइंट से दूसरे प्वाइंट तक सवारी सेवा प्रदान करने के लिए है को वापिस बुराड़ी जांच शाखा में जांच के आदेश जारी किए और साथ ही लिखित घोषणा के साथ नोटिस जारी कर वाहन मालिकों को सूचित किया **"वाहन जिनके जांच प्रमाण पत्र समाप्त हो चुके है या 15 दिन में समाप्त हो रही हैं वह परिवहन विभाग 5/9 अंडर हिल रोड में लिखित फार्म भर कर जमा करे"** (फार्म की कापी सलग्न) साथ ही 20 दिसम्बर 2024 की अखबार की कटिंग जिसमें यह खबर आई।

झूलझूली वाहन जांच शाखा में जब ऑटोमेटिक मशीनों पर वाहनों की जांच करने की क्षमता ही उपलब्ध नहीं जिस कारण वाहन मालिक वाहन की जांच के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर समय (अपॉइंटमेंट) ही प्राप्त नहीं कर पा रहे तो फार्म जमा करने वाले वाहन मालिकों के वाहन परिवहन आयुक्त कहा से जांच करवाएंगे। वाहन मालिकों द्वारा फार्म जमा कराने के बाद वाहन मालिक अब परिवहन विभाग के चक्कर और काटने को मजबूर हो गए और चक्कर काटने पर भी उन्हें उनकी समस्या जो परिवहन आयुक्त ने एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने और गैर कानूनी तरीके से राजस्व में इजाफा करवाने के उद्देश्य के लिए उत्पन्न करी का हल नहीं मिल रहा।

पहले से परेशानी में घिरे वाहन मालिकों को परिवहन विभाग के चक्कर काटने से कितनी और परेशानी बढ़ रही हैं इसको वही समझ सकते है जिनके साथ ऐसा बीता हो।

एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश को क्या समझा और माना जाए आप ही बताए।

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT
JHULJHULI, VEHICLE INSPECTION UNIT, NEW DELHI-110073

NOTICE

ATTENTION VEHICLE OWNERS/DRIVERS

Vehicles owners of vehicles whose fitness certificate has expired or is going to expire in next 15 days may apply at Facilitation Center with the following details:

1. Vehicle Registration number-
2. Chassis Number (Last six digits)-
3. Registered owner name (as per RC)-
4. Category of vehicle (Light Motor vehicle/Heavy Motor Vehicle)-
5. Fitness expiry date-
6. Phone no.-
7. Email address-

(Note: In case the vehicle is attached with the school, the agreement with the school for plying the bus must be attached).

The details can be sent by post at the following address:

To

Facilitation Center (near entry gate no. 1)
Transport Department
5/9 Under Hill Road,
New Delhi-110054

Ordered by
Dy. Commissioner (VIU)

20 दिसम्बर 2024 की अखबार की कटिंग

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

क्या होता है 'गोल्डन आवर' ? सड़क दुर्घटना के बाद अगले 60 मिनट क्यों होते हैं अहम

परिवहन विशेष न्यूज

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोग घायल होते हैं। यदि गोल्डन आवर के महत्व को समझा जाए और आम लोग प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी रखें, तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है।

नई दिल्ली। हाल ही में देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में एक बयान दिया, जो काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन हादसों के दौरान आम नागरिक कैसे मददगार बन सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि 'गोल्डन आवर' का क्या महत्व है?

क्या है 'गोल्डन आवर' और क्यों है यह महत्वपूर्ण?

दरअसल गोल्डन आवर सड़क दुर्घटना के तुरंत बाद के पहले 60 मिनट को कहा जाता है। यह समय बेहद अहम होता है, क्योंकि यदि इस अवधि में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए या उसे प्राथमिक चिकित्सा दे दी जाए, तो उसकी जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इस समय पर सही देखभाल से चोट की गंभीरता को भी कम किया जा सकता है।

गोल्डन आवर के दौरान मरीज को किसी बड़े अस्पताल ले जाना हमेशा जरूरी नहीं होता। उसे सबसे नजदीकी चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाना या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना भी पर्याप्त हो सकता है। लेकिन भारत में एक बड़ी समस्या यह है कि हादसे के समय लोग मदद करने के बजाय मौके पर भीड़ लगाते हैं, जिससे घायल को समय पर इलाज नहीं मिल पाता।

गोल्डन आवर में जान कैसे बचाई जा सकती है?

यदि आप सड़क दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद हैं, तो आप कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाकर किसी घायल व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में:

स्थिति का आकलन करें

सबसे पहले यह देखें कि घायल व्यक्ति का क्या हाल है। क्या वह होश में है और आपकी बात सुन सकता है? यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उसकी सांस चल रही है और वह किसी भी तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है।

एंबुलेंस बुलाएं

अगर आप हादसे की जगह पर हैं, तो सबसे पहले घायल व्यक्ति को और अधिक नुकसान से बचाएं। घायल व्यक्ति तो अपने स्तर से मदद पहुंचाने की कोशिश करें। जरुरत हो तो एंबुलेंस बुलाएं या फिर अपनी गाड़ी या ऑटो की मदद से उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाएं।

सीपीआर (CPR) का उपयोग करें

एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में CPR (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) देना सीखना चाहिए। यह प्रक्रिया मुश्किल नहीं है और इसके लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी उपलब्ध हैं। सीपीआर देने से घायल व्यक्ति के मस्तिष्क और शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जो उसकी जान बचाने में मददगार होती है।

मदद के लिए आगे आएं

यदि आप स्वयं मदद नहीं कर सकते, तो दूसरों को इसकी सूचना दें। जरूरी नहीं कि आप हर कदम खुद उठाएं, लेकिन मदद के लिए प्रेरित करना भी एक बड़ा योगदान हो सकता है।

क्यों है जागरूकता की जरूरत?

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल लाखों लोग घायल होते हैं। यदि गोल्डन आवर के महत्व को समझा जाए और आम लोग प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी रखें, तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस दिशा में जागरूकता फैलाना और सीपीआर जैसी तकनीकों का प्रशिक्षण लेना बेहद जरूरी है।

दिल्ली में वाहनों के पंजीकरण के आंकड़े चिंताजनक, 2024 में 7.8 प्रतिशत तक की वृद्धि

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में 2024 में वाहनों के पंजीकरण में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, हालांकि 2023 के मुकाबले यह मामूली बढ़त है. राजधानी में निजी वाहनों की संख्या में बढ़त देखी गई है. लेकिन सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के पंजीकरण की स्थिति कम है, जो चिंता का विषय है. वर्ष 2024 में कुल 7,09,024 वाहन पंजीकृत हुए और वर्ष 2023 में 6,57,954 वाहन रजिस्टर हुए थे. 2022 में कोरोना काल के बाद वाहन पंजीकरण में 32.6 प्रतिशत की बड़ी छलांग देखी गई थी, तब 6,08,378 वाहन पंजीकृत हुए थे. इसके बाद वर्ष 2023 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी.

2024 में ईंधन के अनुसार कितने वाहन खरीदे गए

किस वर्ष कितने वाहन हुए रजिस्टर्ड

किस वर्ष कितने वाहन हुए रजिस्टर्ड (ETV BHARAT)

2024 में वाहनों के पंजीकरण में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि

2024 में वाहनों के पंजीकरण में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि बीते वर्ष लोगों ने सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन खरीदे. दिल्ली परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में 4,48,767 दोपहिया वाहन पंजीकृत हुए हैं. हल्के मोटर वाहन, जिनमें कार, जीप, वैन, हैचबैक, सेडान, और एसयूवी शामिल हैं, 1,87,286 यूनिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहे.

दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. ऐसे में, यह दिल्ली से बाहर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां खरीदते हैं. इसलिए गिरावट आई है. इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बिक रहे क्योंकि जागरूक हो रहे हैं. यह पर्यावरण के लिए अच्छा है. आबादी बढ़ रही है तो लोग ज्यादा व्हीकल खरीद रहे हैं. फाइनेंस की सुविधा होने की वजह से भी इसमें बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है.

- अनिल चिकारा, रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, दिल्ली परिवहन विभाग

निजी वाहनों की खरीद में हुई भारी बढ़ोतरी

वर्ष 2024 के जनवरी में 67,216 वाहनों की बिक्री के साथ साल की शुरुआत हुई. अक्टूबर और नवंबर में त्योहारों के दौरान बिक्री में उछाल दर्ज की गई. तब क्रमशः 87,988 और 83,361 वाहन पंजीकृत हुए, लेकिन दिसंबर में यह संख्या घटकर 43,538 रह गई. निजी वाहनों की खरीद में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन दिल्ली में प्रीमियम सार्वजनिक परिवहन की कमी है. दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना बेहद जरूरी है क्योंकि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है।

2024 में ईंधन के अनुसार कितने वाहन खरीदे गए

ईंधन	वाहन संख्या
पेट्रोल	5,13,078
इलेक्ट्रिक (बीओवी)	67,493
पेट्रोल/सीएनजी	44,829
सीएनजी	24,642
पेट्रोल हाइब्रिड	18,134
डीजल	12,246
प्योर ईवी	12,178
पेट्रोल/इथेनॉल	11,411
हाइब्रिड ईवी	4,953
डीजल हाइब्रिड	54
एथेनॉल	6

किस वर्ष कितने वाहन हुए रजिस्टर्ड

वर्ष	रजिस्टर्ड वाहन
2020	4,23,544
2021	4,58,919
2022	6,08,378
2023	6,57,954
2024	7,09,024

दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है महाकुंभ मेला

नई दिल्ली। आजकल न केवल देश मे बल्कि विदेशों में भी महा कुम्भ की चर्चा सबकी जुबान पर है। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है। महाकुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। हमारे हिंदू धर्म में इसको अत्यंत पवित्रतम और उच्चतम धार्मिक समागम माना जाता है क्योंकि यह प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर आयोजित किया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थराज यानी की तीर्थ स्थलों का राजा कहा गया है। माना जाता है कि ब्रह्म देव ने सबसे पहला यज्ञ प्रयागराज में ही किया था। वहीं यह भी कहा जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है और उन्हें जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। संभावना है कि इस महाकुंभ में देश-दुनिया से करोड़ों लोग शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज में संगम तट पर नहाने का अपना एक अलग ही महत्व है। प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं।

आइए, जानते हैं कि आखिर इस कुम्भ महोत्सव को इतना दिव्य, भव्य और उच्चकोटि का स्थान क्यों प्राप्त है, तो बता दें कि इसका संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन से अमृत निकाला था तब अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। छिना झपटी के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदे धरती के चार स्थानों पर हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिरी थीं। अमृत के स्पर्श से ये चारो स्थान अमृत तुल्य हो गए थे। अमृत कुछ और नहीं बल्कि भगवान का ही स्वरूप है। समुद्र मंथन के अवसर पर भगवान के पाँच अवतार परिलक्षित होते हैं।

पहला अमृत के रूप में भगवान का प्राकट्य, दूसरा मंदारचल भी भगवान का ही स्वरूप, तीसरा मंदारचल को धारण करने के लिए भगवान का कच्छप अवतार, चौथा अमृतकुम्भ लेकर धन्वन्तरी के रूप में प्राकट्य और पांचवा अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण करना। जिस अमृतकुंभ को प्राप्त करने के लिए भगवान को पाँच-पाँच अवतार लेने पड़े, वह कुम्भ कितना दिव्य भव्य और पवित्र हो सकता है? यह सोच-समझ कर ही प्राचीन काल में हमारे ऋषि-महर्षियों ने इस महाकुंभ की गौरवशाली परंपरा शुरू की होगी। विशेष तिथि, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र में किए गए स्नान ध्यान और जप तप निश्चित ही मानव जाति को अमरत्व प्रदान करते हैं। हमारे मन में यह भी सवाल उठता है कि हर बारह साल के बाद कुंभ मेले का आयोजन क्यों होता है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर बारह दिनों तक युद्ध चला था। देवताओं के बारह दिन मनुष्यों के बारह साल के बराबर माने जाते हैं। इसीलिए हर बारह साल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है।

आइए देखते हैं स्नान की खास तिथियाँ

13 जनवरी 2025- पौष पूर्णिमा

14 जनवरी 2025- मकर संक्रांति

29 जनवरी 2025- मौनी अमावस्या

3 फरवरी 2025- वसंत पंचमी

4 फरवरी 2025- अचला सप्तमी

12 फरवरी 2025- माघी पूर्णिमा

26 फरवरी 2025- महाशिवरात्रि (आखिरी स्नान)

आखिर क्यों नागा साधु पहले 'अमृत स्नान' में स्नान क्यों करते हैं?

आज यानी के मकर संक्रांति पर लाखों लोग महाकुंभ के पहले अमृत स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पर एकत्रित हुए। इस अमृत स्नान में सबसे पहले नागा साधुओं ने स्नान किया है इसके बाद ही आम लोगों ने स्नान किया है। आइए आपको बताते हैं पहले नागा साधु स्नान क्यों करते हैं।

नई दिल्ली। मकर संक्रांति के मौके पर आज महाकुंभ 2025 के पहले अमृत स्नान के दौरान लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए उमड़ पड़े। इस अवसर पर सबसे पहले 13 अखाड़ों के साधुओं ने संगम में डुबकी लगाई, उसके बाद आम लोगों ने डुबकी लगाई। अमृत स्नान, जिसमें नागा साधुओं को सबसे पहले स्नान करने का मौका दिया जाता है। इनको महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण माना जाता है। महाकुंभ के पहले शाही स्नान के लिए नागा साधु ने पहले स्नान किया। दरअसल, 13 अखाड़ों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है, वो इस प्रकार है- उदासीन, बैरागी (वैष्णव), और संन्यासी (शैव)। वैरागी अखाड़े निर्मोही, दिगंबर अनी और निर्वाणी अनी हैं; दो उदासीन अखाड़े (नया और बड़ा); और निर्मला अखाड़ा शैव अखाड़े हैं- महानिर्वाणी, अटल, निरंजनी, आनंद, भैरव, आह्वान और अग्नि।

महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधु डुबकी क्यों लगाते हैं

न्यूज 18 के मुताबिक, लगभग आठवीं शताब्दी से ही विभिन्न अखाड़ों के साधु प्रयागराज में अमृत स्नान करने के लिए एकत्रित होते रहे हैं। अमृत स्नान आदेश, जो कि संघर्ष का स्त्रोत बन गया है। कुंभ के महीने भर चलने पर समारोहों का आयोजन नौवीं और अठारहवी शताब्दी के बीच अखाड़ों के द्वारा आयोजन किया गया है। इन अखाड़ों का अभी भी दबदबा है, अब अमृत स्नान का आदेश पर औपचारिकता मिल चुकी है।

धार्मिक माना मान्यता के अनुसार, पवित्र स्नान करने वाले पहले लोग नागा साधु थे, क्योंकि यह भगवान शिव के शिष्य माने जाते है क्योंकि ये लोग उनके प्रति गहरी तपस्या और भक्ति रखते हैं। यह प्रथा तब से चली आ रही है, जो नागा साधुओं की गहन आध्यात्मिक शक्ति और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। जिन्हें अमृत स्नान का पहला विशेषाधिकार दिया जाता है।

आखिर किन जगहों पर अमृत की बूंदे गिरी थी

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की चार बूंदें चार अलग-अलग स्थानों (प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक) पर गिरी थीं, जब देवता और दानव अमृत कलश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। अब इन स्थानों पर महाकुंभ मेले की स्थापना की जाती है।

स्किन ग्लोइंग से लेकर वजन घटाने में फायदेमंद है पाइनएप्पल सूप, आज ही घर में बनाएं, नोट करें आसान विधि

क्या आप ने कभी पाइनएप्पल का सूप पिया है, अगर नहीं तो इस लेख में हम आपको कुछ फायदे बताने जा रहे हैं, जिसके सेवन से ही आपको काफी लाभ मिलेगा। पाइनएप्पल का सूप स्वाद के साथ ही सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। आइए आपको बताते हैं इसे कैसे बनाएं।

आपने कई सारे सूप पिएंगे होंगे जैसे कि गाजर, टमाटर, मशरुम या अन्य सब्जियों का, लेकिन आप ने कभी भी पाइनएप्पल का सूप नहीं पिया होगा। हालांकि, पाइनएप्पल का सूप स्वाद में काफी टेस्टी होता है और हेल्द के लिए अच्छा होता है। इस सूप के कई अनगिनत फायदे होते हैं। पाइनएप्पल सूप में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और फाइबर इम्यूनिटी बढाने से लेकर डाइजेशन को भी सुधारता है और त्वचा को ग्लोइंग बनाता है।

पाइनएप्पल सूप बनाने के लिए सामग्री

- 1 कप कटा हुआ ताजा पाइनएप्पल
- 1 बारीक कटा हुआ प्याज
- 1 कटी हुई गाजर
- 2 कप पानी
- 1 चम्मच मक्खन
- 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर
- नमक स्वादानुसार
- धनिया पत्ती गर्निश करने के लिए

पाइनएप्पल सूप बनाने का तरीका

- सबसे पहले आप एक पैन में मक्खन गर्म करके उसमें प्याज, अदरक और गाजर डालकर हल्का भून लें। अब आप पैन में कटा हुआ पाइनएप्पल डालकर सभी चीजों के साथ 2-3 मिनट तक पकाएं।
- फिर पैन में थोड़ा सा पानी डालकर 10 मिनट तक सभी चीजों को लो फ्लेम पर उबलने दें। इसके बाद गैस बंद कर दें मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें।
- जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को मिक्सी में पीस लें और फिर छानकार वापस पैन में डालकर पकाएं।
- पैन में काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर सूप के मिश्रण को 2 मिनट तक और पकाएं। अब गैस बंद कर दें। आपका टेस्टी और हेल्दी पाइनएप्पल सूप तैयार है। गर्निश के लिए आप धनिया की पत्ति डाल सकते हैं।

पाइनएप्पल सूप पीने के फायदे

- पाइनएप्पल सूप पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, इसमें मौजूद विटामिन सी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे सर्दी-जुकाम में राहत मिलता है।
- पाइनएप्पल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को डैमेज से बचाकर उसका नेचुरल ग्लो बनाए रखता है।
- पाइनएप्पल सूप में कम कैलोरी और हाई फाइबर मौजूद होता है। फाइबर पेट के लंबे समय तक भरा रखता है। जो वेट लॉस में मदद करता है।

गूगल पे के यूजर्स के लिए वरदान है ये सीक्रेट ट्रिक, आप भी उठा सकते हैं फायदा, फॉलो करें ये सिंपल से स्टेप

गूगल पे यानी गूगल पे यूजर्स को कई शानदार फीचर ऑफर करता है। ऑटोपे फीचर भी इन्हीं में से एक है। इस फीचर की मदद से यूजर अपने रेकरिंग ट्रांजैक्शंस जैसे सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल और दूसरी सर्विसेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सर्विस को यूज नहीं करते, लेकिन ऑटोपे के चलते हर महीने अकाउंट से पैसे कट जाते हैं।

ऑनलाइन पेमेंट्स या डिजिटल पेमेंट्स के लिए कई लोग गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे यानी गूगल पे यूजर्स को कई शानदार फीचर ऑफर करता है। ऑटोपे फीचर भी इन्हीं में से एक है। इस फीचर की मदद से यूजर अपने रेकरिंग ट्रांजैक्शंस जैसे सब्सक्रिप्शन, यूटिलिटी बिल और दूसरी सर्विसेज को ऑटोमेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सर्विस को यूज नहीं करते, लेकिन ऑटोपे के चलते हर महीने अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। कुछ यूजर ऑटोपे को कैंसल करना भूल जाते हैं, तो कुछ को इसका तरीका नहीं पात होगा।

अगर आप भी गूगल पे पर रजिस्टर्ड किसी ऑटोपे को कैंसल करना चाहते हैं जिससे आपके फिजूल पैसे ना कटें तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। जिससे आप ऑटोपो को कैंसल कर सकेंगे।

इन स्टेप्स को करें फॉलो

सबसे पहले अपने डिवाइस पर गूगल पे को ओपन करें।

फिर ऑटोपे सेटिंग्स में जाएं, जहां आपको टॉप राइट साइट में मौजूद अपने प्रोफाइल फोटो को टैप करना है।

अब ऑटोपे सेलेक्ट करें और सब्सक्रिप्शन को सर्च करें।

इसमें आपको आपके एक्टिव ऑटोपे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट दिखेगी। इनमे से आप उस सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करें, जिसे आप कैंसल करना चाहते हैं।

सब्सक्रिप्शन को कैंसल करने के लिए कैंसिल ऑटोपे पर टैप करें।

यहां आपसे कैंसल रिक्वेस्ट को कन्फर्म करने के लिए भी कहा जा सकता है।

कन्फर्मेशन के लिए यूपीआई पिन एंटर करना होगा।

कन्फर्मेशन के बाद कैंसलेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुट हो जाएगा।

हालांकि, ऑटोपे कैंसलेशन का टाइम या इफेक्टिव डेट मर्चेंट के ऊपर निर्भर करेगा। कुछ मामलों में गूगल पे ऐप से ऑटोपे कैंसल करने के बाद भी सब्सक्रिप्शन कैंसल करने के लिए आपको मर्चेंट से कॉन्टैक्ट कनरा पड़ सकता है। अगर सब्सक्रिप्शन का पेमेंट शेड्यूल है, तो ये कैंसलेशन से पहले प्रोसेस भी हो सकता है।

सुबह उठते ही फोन देखना बंद करें, जानिए इसके नुकसान

सुबह उठते ही स्मार्टफोन देखने से सबसे पहला असर हमारी नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है। जब हम सोते हैं, तो हमारा दिमाग शांत और रिलैक्स्ड स्थिति में होता है। लेकिन जैसे ही हम सुबह स्मार्टफोन देखते हैं, हमारा दिमाग अचानक सक्रिय हो जाता है, जिससे ब्रेन की नसों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है।

आज की डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है, जिसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल है। चाहे काम हो, मनोरंजन, या जानकारी हासिल करना, स्मार्टफोन का उपयोग हर क्षेत्र में बढ़ गया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सुबह उठते ही स्मार्टफोन की स्क्रीन देखने से आपकी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह आदत न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि मानसिक शांति और दिनभर की उत्पादकता को भी कम कर सकती है।

सुबह उठते ही स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के नुकसान

सुबह उठते ही स्मार्टफोन देखने से सबसे पहला असर हमारी नींद की गुणवत्ता पर पड़ता है। जब हम सोते हैं, तो हमारा दिमाग शांत और रिलैक्स्ड स्थिति में होता है। लेकिन जैसे ही हम सुबह स्मार्टफोन देखते हैं, हमारा दिमाग अचानक सक्रिय हो जाता है, जिससे ब्रेन की नसों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। यदि यह आदत लंबे समय तक जारी रहती है, तो आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है, और आप दिनभर थकावट और सुस्ती महसूस कर सकते हैं।

इसके अलावा, सुबह-सुबह फोन पर सोशल मीडिया, ईमेल या न्यूज देखने से स्ट्रेस और नेगेटिविटी बढ़ सकती है। नेगेटिव खबरें देखकर दिमाग में नेगेटिव विचार आ सकते हैं, जिससे पूरे दिन का मूड खराब हो सकता है। इसके साथ ही, इस आदत का सीधा असर आपकी उत्पादकता पर भी पड़ता है। सुबह का समय दिन की प्लानिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन स्मार्टफोन के कारण हमारा ध्यान भटक जाता है और कीमती समय बर्बाद हो जाता है।

स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों के लिए बेहद हानिकारक होती है। सुबह-सुबह इसका इस्तेमाल आंखों में जलन, सूजन और धुंधलेपन जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। लंबे समय तक इस आदत को जारी रखने से आंखों की रोशनी कमजोर होने का खतरा भी बढ़ सकता है।

सुबह उठते ही स्मार्टफोन देखने की आदत के प्रभाव को कैसे कम करें?

इस आदत से बचने के लिए आपको अपनी सुबह की दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव करने होंगे। सुबह उठने के बाद योग, ध्यान, या व्यायाम जैसी गतिविधियों से दिन की शुरुआत करें। यह न केवल आपके शरीर को फिट रखेगा, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, डिजिटल डिटॉक्स अपनाकर सोने से पहले और जागने के बाद कम से कम 30 मिनट तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करें।

सुबह के समय कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें, जैसे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, या एक कप चाय के साथ खुद को समय देना। यह आपको दिनभर ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस कराने में मदद करेगा। साथ ही, अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करें, जो आपकी स्मार्टफोन उपयोग की आदतों को सुधारने में मदद करेगा।

एक और आसान उपाय यह है कि रात को सोने से पहले फोन को बेडरूम से बाहर रखें। इससे सुबह उठते ही फोन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह छोटा सा बदलाव आपकी सेहत और दिनचर्या पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

आदत में बदलाव के लाभ

सुबह की शुरुआत में योग और ध्यान करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह दिमाग को शांत रखता है और आपको तनाव से दूर रखने में मदद करता है। शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए नियमित व्यायाम सबसे अच्छा विकल्प है, जो स्मार्टफोन पर समय बर्बाद करने से भी बचाता है।

सुबह स्मार्टफोन न देखने की आदत से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। आप ताजगी और नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही, आंखों पर पड़ने वाला तनाव कम होता है, जिससे आपकी आंखों की सेहत लंबे समय तक बेहतर बनी रहती है।

स्मार्टफोन आज हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसकी लत हमारी सेहत और मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकती है। सुबह उठते ही फोन का इस्तेमाल करने की आदत न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक रूप से भी नुकसान पहुंचा सकती है। अपने दिन की शुरुआत योग, ध्यान और पॉजिटिव गतिविधियों से करें। डिजिटल डिटॉक्स को अपनाकर अपने स्मार्टफोन उपयोग पर नियंत्रण रखें। यह छोटे-छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता ला सकते हैं। याद रखें, आपका स्वास्थ्य और मानसिक शांति किसी भी टेक्नोलॉजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने स्मार्टफोन को अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें।

अब रमेश बिधूड़ी कह रहे कि वह सीएम चेहरा नहीं हैं तो फिर भाजपा बिना दुल्हे की बारात लेकर कहां जा रही है?- संजय सिंह

सुषमा रानी

नई दिल्ली। 14 जनवरी आम आदमी पार्टी ने एक फिर सीएम चेहरा को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। ''आप'' के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा को दिल्ली की जनता को बताना चाहिए कि अगर रमेश बिधूड़ी उसका मुख्यमंत्री चेहरा नहीं हैं तो फिर कौन है? पिछले दिनों रमेश बिधूड़ी को भाजपा का सीएम चेहरा बनाने को लेकर चर्चा शुरू हुई तो उसके नेताओं के बीच झगड़े शुरू हो गए। ''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम चेहरा अरविंद केजरीवाल ने रमेश बिधूड़ी को डिबेट की खुली चुनौती थी और पूछा था कि दिल्ली को लेकर उनका विजन क्या है, लेकिन अब रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि वह सीएम चेहरा नहीं है, तो फिर भाजपा बिना दुल्हे की बारात लेकर कहां जा रही है?

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि दो-तीन दिन पहले आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के नेता रमेश बिधुड़ी को खुलेआम चुनौती दी थी। उन्होंने भाजपा के सीएम चेहरा रमेश बिधूड़ी से पूछा था कि दिल्ली को लेकर उनका विजन क्या है और वह दिल्ली के बारे में क्या सोचते हैं? इस विषय पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वह रमेश बिधूड़ी से सार्वजनिक मंच डिबेट करना चाहते हैं।

संजय सिंह ने कहा कि रमेश बिधूड़ी भाजपा में मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार हैं। रमेश बिधूड़ी के अंदर वह सारी योग्यता है, जो भाजपा में मुख्यमंत्री बनने के लिए चाहिए। वह सब कुछ रमेश बिधूड़ी के पास मौजूद है। जब हमें सूत्रों से पता चला कि भाजपा में रमेश बिधूड़ी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा है तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की। अरविंद केजरीवाल की प्रेसवार्ता के बाद भाजपा के लोग आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिए। सीएम चेहरा बनने के लिए भाजपा के नेता आपस में लड़ना शुरू कर दिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। साथ ही कई अन्य नेताओं ने भी अपनी दावेदारी पेश की।

उन्होंने कहा कि अब पता चल रहा है कि रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि वह भाजपा के सीएम चेहरा नहीं है। अगर रमेश बिधूड़ी सीएम चेहरा नहीं है तो भाजपा को बताना चाहिए कि उनका दूल्हा कौन है? बिना दूल्हे की बारात लेकर भाजपा कहां जा रही है? बिना दूल्हे की बारात लेकर भाजपा दिल्ली की जनता को क्या बताना चाह रही है? फिर तो यह बहुत ही खतरनाक बात है कि चुनाव हो जाएगा और चुनाव तक दिल्लीवालों के यह पता ही नहीं चलेगा कि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? दिल्लीवालों को पता नहीं चलेगा कि भाजपा का सीएम चेहरा कौन है?

संजय सिंह ने कहा कि भाजपा को दिल्ली की जनता को यह बताना चाहिए कि उनका दूल्हा कौन है। सीएम चेहरा कौन है? रमेश बिधूड़ी के ऊपर दबाव बनाकर उनसे बयान क्यों दिलवाया गया कि वह मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है? अगर वह मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो फिर भाजपा का चेहरा कौन है, यह दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती है।

मैंने अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ अपना नामांकन दाखिल किया: सीएम आतिशी

मुख्य संवाददाता/ सुषमा रानी

नई दिल्ली। 14 जनवरी आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को कालकाजी विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ₹मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की राजनीति को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ, मैंने कालकाजी से अपना नामांकन दाखिल किया। पिछले पांच वर्षों में कालकाजी के लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे विश्वास है कि इस चुनाव में भी उनका आशीर्वाद मिलेगा।

नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम आतिशी ने कहा, ₹इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैंने कालकाजी विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह पिछले पांच वर्षों में कालकाजी के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से मुझे बहुत स्नेह और समर्थन मिला है, उसी तरह आगामी चुनाव में भी मुझे यहां के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा।

सीएम आतिशी ने अपने एक्स(ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि, ₹आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की राजनीति को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ, कालकाजी से अपना नामांकन दाखिल किया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अरविंद केजरीवाल पर दिए गए बयान को लेकर आतिशी ने कहा, ₹यह सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे होता है कि जब कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत करने के लिए एलजी के पास जाते हैं, तो उन्हें तुरंत समय दे दिया जाता है। उनकी शिकायत स्वीकार कर ली जाती है। तुरंत कार्रवाई होती है और उस पर एफआईआर दर्ज होती है। जबकि विधायकों को अपने इलाके के काम के लिए एलजी साहब से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। जब विधायक समय मांगते हैं, तो एलजी साहब समय नहीं देते।

आतिशी कितनी अमीर, क्या सच में नाम के पीछे लगता है 'मार्लेना'? एफिडेविट से खुल गया राज

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-DL17457942700436X
Certificate Issued Date	:	13-Jan-2025 12:40 PM
Account Reference	:	IMPACC (IV)/ dl1040103/ DELHI/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-DLDL10401038029041836092 1X
Purchased by	:	ATISHI MARLENA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	ATISHI MARLENA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	ATISHI MARLENA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली चुनाव 2025 में कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी मार्लेना ने अपने चुनावी खर्च के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है। इसी बीच उनके चुनावी हलफनामे से उनके सरनेम और कुल संपत्ति का खुलासा हुआ है। बीते दिन दिल्ली की सियासत भी उनके सरनेम को लेकर खूब गरमाई।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहीं आतिशी ने अपने चुनाव खर्च के लिए क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत की है। जनता से चंदा मांग रहीं आतिशी की कुल दौलत पता चल गया है। दूसरे शब्दों में कहे तो आतिशी के पास कितनी संपत्ति है। उसका पता चला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनके सरनेम को लेकर भी कंफ्यूजन दूर हो गया है। आतिशी अपने सोशल मीडिया पर भी सरनेम नहीं लिखती हैं।

दिल्ली की राजनीति भी आतिशी के सरनेम को लेकर गरमाई

आतिशी ने जो चुनावी हलफनामा भरा है। उसके आधार पर उनका पूरा नाम आतिशी मार्लेना ही है। ये बात अलग है बीते कुछ सालों से उनके नेम प्लेट पर सिर्फ आतिशी ही दिखता था। जिसके बाद लोगों में चर्चा का विषय बना कि आतिशी मार्लेना हैं या सिंह?

बता दें बीते दिन दिल्ली की राजनीति आतिशी के सरनेम को लेकर गरमाई भी थी। जहां पर कालका जी सीट से भाजपा प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी आतिशी के सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी।

आतिशी के पास 76 लाख 93 हजार से अधिक की संपत्ति

चुनावी हलफनामे में आतिशी ने अपनी कुल संपत्ति 76 लाख 93 हजार 374 रुपये और 98 पैसे बताया है। जिसमें 30 हजार रुपये कैश और 1 लाख रुपये के गहने भी शामिल हैं। आतिशी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक उनके पास कोई चल और अचल संपत्ति भी नहीं है और ना ही उनके पास अपना कोई घर और कार है।

आपका वोट आपके बच्चों और देश का भविष्य तय करता है, किसी को भी वोट दे देना, लेकिन वोट ख़रीदने वाले को मत देना- केजरीवाल

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों से पैसे से वोट खरीद रही भाजपा को सबक सिखाने की अपील की है। उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि आपका वोट हीरे से भी कीमत है। इसलिए किसी भी कीमत पर अपना वोट बिकने मत देना। गाली-गलौज पार्टी वाले खुलेआम कह रहे हैं कि पैसे से दिल्लीवालों के वोट खरीद लेंगे। मेरी अपील है कि इस बार इन्हें बता दो कि दिल्लीवाले बिकाऊ नहीं हैं। इनके पास बहुत पैसा हो गया है। अब इन्होंने सोने की चैन बांटने को भेजी है, लेकिन इनके नेता बांट नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे, कंबल, साड़ी, चादर, सोने की चेन बांटने वाले देश के गद्दार हैं। आप इनसे सब ले लो, लेकिन इनको कभी वोट मत देना। आपका वोट आपके बच्चों और देश का भविष्य तय करता है। इसलिए किसी को भी वोट दे देना, लेकिन वोट ख़रीदने वाले को वोट मत देना।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, यह साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनने जा रही है। समय बीतने के साथ-साथ आम आदमी पार्टी का ग्राफ भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं, ऐसा लगता है कि गाली गलौज पार्टी ने अपने हथियार डाल दिए हैं। इनके पास नैरेटिव, विजन और सीएम का चेहरा इनमें से कुछ भी नहीं है। लिहाजा अब ये बेईमानी पर उतर आए हैं। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं। लेकिन जो पैसे बांटे गए, उससे लोगों में बहुत असंतोष है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इनकी पार्टी ने ऊपर से 10-10 हजार रुपए लोगों में बांटने के लिए भेजे। लेकिन इनके नेताओं को यकीन है कि उनको जीत मिलनी नहीं है। इसलिए इस चुनाव में पैसे ही कमा लिए जाएं। इसलिए इनके नेताओं ने 9 हजार रुपए अपने पास रख लिए और जनता को 1,000-1,000 रुपए बांट दिए। इन लोगों ने यह पैसे सबको नहीं दिए। जिसके चलते जनता में भारी रोष है कि इनके नेता 9-9 हजार रुपए खा गए। जहां भी इनके नेता जा रहे हैं, जनता उनसे कह रही है कि हमारे पैसे दो, उसके बाद अपनी बात कहना। जिन इलाकों में इनके नेताओं ने पैसे नहीं बांटे उन इलाकों के लोगों में रोष है कि उनके पैसे कहां गए।

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि इनकी पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे। इनके नेताओं ने एक कॉलोनी में कंबल बांटे लेकिन बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे। इसलिए बगल वाली कॉलोनी के लोग पूछ रहे हैं कि उनके कंबल कहां गए? चादरें भी एक कॉलोनी में बांटी लेकिन बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटी। तो उस कॉलोनी के लोग भी पूछ रहे हैं कि हमारी चादरें कहां गईं? ऊपर से पार्टी ने सभी इलाकों में साड़ी बांटने के लिए भेजी थी लेकिन एक कॉलोनी में बांटी और बाकियों में नहीं बांटी। बाकी खा गए। इनकी पार्टी ने जूते भेजे, इन्होंने तीन या चार कॉलोनी में जूते बांटे लेकिन बाकियों में नहीं बांटे। ये लोगों के जूते और जैकेट भी खा गए। सभी को नहीं बांटे। इसलिए इनके नेता जहां जा रहे हैं उनसे जनता पूछ रही है कि हमारे नाम के आए हुए पैसे कहां हैं? हमारे नाम के आए हुए जूते, जैकेट, साड़ी, कंबल और चादरें कहां हैं? जनता अब इनके दफ्तरों में जा रही है और इनके नेताओं से लड़. रही है। जो लोग दफ्तरों में जाते हैं उनका मुंह बंद कराने के लिए उसे पैसे और सामान दे देते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब पता चला है कि एक-दो दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी शुरू की है। सोने की चैन एक-दो कॉलोनियों में ही बंटी है और धीरे-धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बंट रही है। इनके नेता सोने की चैन भी खा गए, वो भी नहीं बांटी। इनके नेता सभी की सोने की चैन खा गए। तो इनके नेता बताएं कि सारे पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी और सोने की चैन कहां गई? जनता में क्यों नहीं बांटी गई? इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि हम दिल्ली वालों को तो खरीद लेंगे। हम दिल्ली वालों के वोट खरीद लेंगे। क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि ये हार गए हैं। मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूं कि ये जो बांट रहे हैं, वह सब ले लो। इनके दफ्तरों में जाकर लड़-झगड़कर ले लो। लेकिन किसी भी हालत में अपना वोट मत बिकने देना। हमारा वोट बहुत कीमती है। हमारे वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी को वोट दो। मेरी जनता से अपील है कि पैसे, कंबल, साड़ी और चादर बांटने वाले को कतई वोट मत देना। ये देश के गद्दार हैं। ये देश को खरीद रहे हैं। इन्हें इतना अहंकार हो गया है कि इन्हें लगता है कि ये देश को खरीद सकते हैं। जो आपके वोट को पैसे बांटकर खरीदने की कोशिश करे, उनसे सब कुछ ले लो, इस बार उनका पैसा बर्बाद कर दो। जितना पैसा बांट रहा है, इनसे और पैसे खर्च करवाओ। इनका सारा पैसा लूटवा दो, लेकिन इन्हें वोट मत देना। इन्हें दिखा दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता है। इस बार इन पैसों वालों, बेईमानों और गुंडों को बता दो कि दिल्ली के लोग और उनका वोट बिकाऊ नहीं है। इस बार इन्हें दिखा दो कि भारत और भारत का जनतंत्र बिकाऊ नहीं है। भारत को खरीदने वाला अभी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस सिस्टम को बदलना है। सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता में आओ, बेईमानी से पैसा कमाओ और फिर वोट खरीद लो और चुनाव जीत लो। हम सब लोगों को इस सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना है। दिल्ली की जनता इस बार पूरे देश को एक मिसाल पेश करेगी। दिल्ली शरीफों, अच्छे और सभ्य लोगों का शहर है। इन लोगों को लगता है कि ये दिल्ली के लोगों को खरीदेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि इस बार दिखा दो कि आप बिकाऊ नहीं हो। अगर आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार पैसे या सामान बांटे तो उसे वोट मत देना, उसे भी हरा देना। हम यहां पर चुनाव जीतने या हराने के लिए नहीं आए हैं। हम देश को बदलने के लिए आए हैं। सड़ी गली व्यवस्था को बदलने के लिए आए हैं।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि गाली-गलौज पार्टी वालों के पास बहुत बहुत पैसा हो गया है। अब इन्होंने अपने नेताओं को सोने की चैन बांटने को भेजी हैं।

आपदा से भाजपा ही दिल्ली वासियों को मुक्ति दिला की सकती है : सांसद भोला सिंह

मुख्य संवाददाता सुषमा रानी

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह ने आज दिल्ली के करोल बाग विधानसभा में एक जनसभा में केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली में जो आपदा पिछले 10 सालों से दिल्ली वीडियो पर आई हुई है उससे मुक्ति दिलाने का कम मात्रा भाजपा ही कर सकती है और दिल्ली में 40% अनुसूचित जाति समाज के लोग रहते हैं उन्होंने भाजपा से वादा किया है कि वह इस आपदा को भागने का कार्य भाजपा के साथ मिलकर करेंगे यह आपदा दिल्ली की जनता को बर्बाद कर रही है और बीमार कर रही है इसका जाना आप लगभग तय है।

इस मौके पर सांसद भोला सिंह ने कहा कि मात्र राजनीति के चलते केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे की झूठी कसम खाते हुए उनसे वादा किया था कि वह दिल्ली से कांग्रेस के घोटाले की पोल खोलेंगे और उनके नेताओं को जेल भेजेंगे परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया कांग्रेस के साथ ही मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और खुद भ्रष्टाचार में डूब गए उन्होंने अन्ना हजारे के साथ वादा खिलाफी की और उनके नक्शे कदम पर नहीं चल केजरीवाल ने जनता के सामने यह भी वादा किया था कि वह सरकारी गाड़ी सरकारी बंगला सरकारी सिक्योरिटी पुलिस नहीं लेंगे क्योंकि वह एक आम आदमी है और उनकी पार्टी आम आदमी है उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं*

इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंच पर बोलते हुए कहा कि ने केजरीवाल के झूठे वादे झूठी कसमें कहां गई आज उनके पास उन्होंने सरकारी बंगला भी लिया सरकारी सुख सुविधा भी ली सरकारी शीश महल भी बनाया और सरकारी पुलिसकर्मी आदि सुख सुविधा भी लेकर घूम रहे हैं मेरा मानना है कि केजरीवाल जैसा की गिरगिट होता है इस प्रकार वह इस राजनीति में पड़कर गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं और जनता से झूठे वादे कर रहे हैं दिल्ली की जनता को आज तक उन्होंने फ्री बिजली का वादा किया था वह नहीं मिल रही है फ्री पानी देने का वादा किया था वह गटर का मिल रहा है पीने का पानी दिल्ली की जनता को नहीं मिल रहा है दिल्ली की जनता पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है और जो इनके मोहल्ला क्लीनिक है वह नशेखोरियों नशेडियों का अड्डा बना हुआ है उसमें डॉक्टर नहीं है कोई बेहतरीन चिकित्सा सुविधा नहीं है सिर्फ नाम के मोहल्ला क्लीनिक रह गए हैं जगह-जगह मोहल्ला क्लीनिक खाली पड़े हैं उनमें गली के कुत्ते सोते रहते हैं अगर केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता को कुछ दिया है तो फ्री की शराब दी है और शराब को पीकर दिल्ली की जनता ने साड़ी बन गई है उनके घर में चूल्हा तक नहीं चल रहा है*

उनकी सरकार अब जाने वाली है जनता समझ चुकी है जनता को पूरी तरह केजरीवाल सरकार ने ठगा है झूठे वादे किए हैं और बार-बार गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले केजरीवाल अब दिल्ली से विदा होने वाले हैं*

इस मौके पर भाजपा करोल बाग से अनुसूचित जाति के दिग्गज नेता में प्रत्याशी दुष्यंत गौतम ने कहा कि दिल्ली के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को आज तक कोई भी लाभ केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया है इस समाज के किसी भी बच्चों को उन्होंने नौकरियों पर नहीं लगाया है ना ही सफाई कर्मचारियों की नौकरियों की भर्ती पूरे 10 साल में इन्होंने निकाली है और कहते हैं झाड़ू का निशान है और झाड़ू सफाई करने के काम आती है दलित समाज की यह रोजी-रोटी का जरिया है आज तमाम अनुसूचित जाति वर्ग इसी झाड़ू से केजरीवाल सरकार का सफाया करने जा रहा है और भाजपा का कमाल अब तमाम दलित समाज मिलकर के खिलाने जा रहा है*

इस मौके पर मीडिया सह प्रमुख कार्यक्रम जिला करोल बाग के जिला मीनाक्षी सूद के सौजन्य से किया गया*

हरीश गिल संजू संगत किशोर कुमार मीना कुमार सरोज वोहित

राम कुमार वर्मा प्रवासी प्रभारी

*सोमनाथ वाल्मीकि शैलेंद्र सिंह अंजू जाटव रीना रानी एवम बूथ प्रबंधन संयोजक करोल बाग शादीपुर पटेल नगर मण्डल जिला करोल बाग दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा की तमाम टीम आदि ने बढ़-चढ़कर के हिस्सा लिया।

दिल्ली भागीदारी एलायंस ने दिल्ली की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे

सुषमा रानी

नई दिल्ली :आज डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली में भिन्न-भिन्न राजनैतिक दलों के साझा मंच, दिल्ली भागीदारी एलायंस के बैनर तले एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय महासंघ पार्टी, भारतीय लिबरल पार्टी, नेशनल यूथ पार्टी, पीस पार्टी, भीम सेना, इंसाफ पार्टी और जय प्रकाश जनता दल जैसे दर्जनों दलों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करके दिल्ली की सभी 70 विधान समाओं पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की।

दिल्ली भागीदारी एलायंस के संयोजक इंजीनियर डी.सी. कपिल ने बताया कि इस गठबंधन में शामिल सभी राजनैतिक दलों ने अलग-अलग विधान सभाओं पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची घोषित की। साथ ही साथ एक दूसरे के ईमानदार सहयोगी बनकर सहयोग करने की भी घोषणा की।

दिल्ली की वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए एलायंस के संयोजक इंजी. डी.सी. कपिल ने फ्री की रेवडियों बांटकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पार्टी ने 2013, 2015 और 2020 के चुनावी घोषणा-पत्रों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, जन लोकपाल नियुक्त करने, यमुना की सफाई, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, दो लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देने और दिल्ली से भ्रष्टाचार मिटाने जैसे जितने भी वायदे किये थे, उन सभी पर दिल्ली सरकार पिछले 11 वर्षों के शासनकाल में बुरी तरह से विफल रही है।

राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आनन्द ने दिल्ली सरकार पर दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी होने के गंभीर आरोप लगाये।

पीस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हाफीज गुलाम सरवर ने अल्पसंख्यकों की हकमारी और उर्दू भाषा को समाप्त करने तथा वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली मस्जिदों के इमामों को पिछले 18 महीने से सैलरी न देने का आरोप लगाया। राज्य सभा मे मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व न देने और कोरोनाकाल में तब्लिकी जमात पर कोरोना फैलाने के झूठे आरोप लगाने का मामला भी उठाया।

प्रेस वार्ता में भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झा, भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर साल्वे, भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अखबर खान राणा, इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर शेख कलीमुद्दीन, जय प्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र पांडे और नेशनल यूथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रजनीश झा ने भाग लिया और प्रेस को सम्बोधित किया।

दिल्ली भागीदारी एलायंस ने दिल्ली की सभी 70 विधान सभाओं पर चुनाव प्रत्याशियों की सूची जारी की। दिल्ली की सभी विधान सभाओं में दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में वादा खिलाफी की शव यात्रा निकालने की भी घोषणा की गई।

नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में बीएमटी यूनिट तैयार, अब नहीं जाना होगा दिल्ली और लखनऊ

बच्चों के इलाज के लिए अब नोएडावासियों को दिल्ली और लखनऊ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। थैलेसिमिया और हीमोफिलिया समेत 30 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बाल मरीजों का इलाज नोएडा में ही हो सकेगा। चाइल्ड पीजीआइ में बीएमटी यूनिट तैयार हो गई है। अस्पताल के चौथे तल पर आठ बेड की यूनिट बनाई गई है। यह यूनिट करीब चार करोड़ से बनाई गई है।

नोएडा। थैलेसिमिया और हीमोफिलिया समेत 30 गंभीर बीमारियों से ग्रस्त प्रदेश के बाल-मरीजों को अब बोनमेरो ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली एम्स व लखनऊ के एसजीपीजीआई के चक्कर नहीं काटने होंगे।

चार करोड़ से बनाई गई है यूनिट

सेक्टर-30 के चाइल्ड पीजीआई में करीब चार करोड़ रुपये की लागत से आठ बेड की बोनमेरो ट्रांसप्लांट (बीएमटी) यूनिट बनाई गई है। 15 जनवरी को उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक यूनिट का फीता काटकर उद्घाटन करेंगे।

खास बात है कि चौथे तल पर यूनिट में बीएमटी के लिए तीन डॉक्टर और 30 नर्स व अन्य स्टाफ की नियुक्ति भी हो गई है। उद्घाटन के दिन से ही यहां यूनिट काम करने लगेगा। वहीं, जिला अस्पताल में डीएनबी छात्र-छात्राओं के लिए एकेडमिक जोन व नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए एसएनसीयू का भी उद्घाटन होगा।

आठ बेड पर मिलेगी ट्रांसप्लांट की सुविधा

अस्पताल के निदेशक प्रो डॉ. अरूण कुमार सिंह ने बताया कि लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट के बाद नोएडा स्थित चाइल्ड पीजीआई में बाल मरीजों में बोनमेरो ट्रांसप्लांट की सुविधा बढ़ाई है। पहले सिर्फ एक बेड पर मरीज का इलाज किया जाता था। अब आठ बेड पर ट्रांसप्लांट की सुविधा दी जाएगी।

उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक देंगे सौगात

चौथे तल पर यूनिट में हीमोटोलाजी आन्कोलाजी की विशेषज्ञ डॉ. नीता राधाकृष्णन के साथ दो चिकित्सक और 30 स्टाफ नर्स को नियुक्त किया है। यूनिट शुरू करने के लिए अधिकारियों से वार्ता की थी। तय हुआ कि उप-मुख्यमंत्री बृजेश पाठक फीता काटकर यूनिट का शुभारंभ करेंगे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह व अन्य पार्टी नेता भी रहेंगे।

यूनिट में बाल मरीजों के लिए अलग कमरा बनाकर बेड व सभी इमरजेंसी व्यवस्थाएं की हैं। बीमारी से ध्यान खींचने के लिए एक और पांच नंबर कमरे में दीवारों पर समुंद्र की खोज, दो व छह नंबर कमरों में मोगली की दुनिया, तीन और सात नंबर कमरों में मिशन मंगल जबकि चार व आठ नंबर कमरे में लहरों की सवारी शीर्षक के साथ पेटिंग बनाकर कार्टूनों की कहानी दर्शायी है।

मरीज और अभिभावकों के लिए तैयार 100 सवाल-जवाब की किताब

डॉ. नीता ने बताया कि थैलेसिमिया और अन्य गंभीर बीमारी में बाल-मरीजों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे 100 सवालों पर 100 जवाब के साथ किताब तैयार की है। जिसका शीर्षक जियो और जीने दो रखा है।

हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में इस किताब को भी मुख्य अतिथि बृजेश पाठक और अन्य अतिथि कार्यक्रम में लॉन्च करेंगे। डॉ. नीता का कहना है कि यूनिट तैयार होते ही दिल्ली व उत्तर प्रदेश के अन्य अस्पतालों से बीएमटी के लिए काल आनी शुरू हो गई हैं जबकि अस्पताल में ही बाल-मरीजों के ट्रांसप्लांट के लिए करीब 60 की वेटिंग चल रही है।

जिला अस्पताल में भी एकेडमिक जोन और एसएनसीयू होगी शुरू

सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में भी उप मुख्यमंत्री डीएनबी छात्र-छात्राओं के लिए एकेडमिक जोन, नवजात शिशुओं के लिए बनी 12 बेड की एसएनसीयू का भी फीता काटकर उद्घाटन करेंगे। सीएमएस डा. रेनू अग्रवाल व अन्य प्रबंधन के लोग तैयारियों में जुटे हैं।

सभी विभागों के रजिस्टर व रिकार्ड पूरा करने में डॉक्टर व स्टाफ लगे हैं। करीब 10 लाख रुपये की लागत से एसएनसीयू बनाई है। इसमें स्टाफ व डॉक्टरों को अपाइंट कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि जिला अस्पताल में अन्य सुविधाओं के लिए भी उप मुख्यमंत्री से मांग हो सकती है। हालांकि, अभी अधिकारी कुछ बता नहीं रहे हैं।

नोएडा में कल से खुलेंगे क्लास 1 से आठ तक के सभी स्कूल, डीएम ने दिया आदेश

नोएडा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते बंद चल रहे कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल बुधवार 15 जनवरी से फिर से खुल जाएंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले कड़ाके की ठंड के कारण कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया था।

ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर जिले के कक्षा एक से आठ तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बुधवार से सुबह नौ बजे से खुलेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार के मुताबिक, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड समेत अन्य बोर्ड के अंतर्गत संचालित स्कूलों के प्रधानाचार्य व प्रबंधकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

बताया 15 जनवरी से सुबह 9 बजे से कक्षाएं संचालित होंगी। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इससे पहले नोएडा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के चलते कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में 3 जनवरी से छुट्टियां घोषित कर दी गई थी।

गाजियाबाद में फिर जमकर गरजा बुलडोजर, कार्रवाई से लोगों में मचा हड़कंप; अरबों की जमीन पर है अवैध कब्जा

गाजियाबाद के विजय नगर में दूसरे दिन भी प्रशासन और पुलिस की बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। विजयनगर में रक्षा संपदा की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। दो दिन से चल रही बुलडोजर कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आगे विस्तार से पढ़िए।

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के विजय नगर में दूसरे दिन भी प्रशासन और पुलिस की बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। दूसरे दिन विजयनगर में रक्षा संपदा की जमीन पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया।

इस दौरान कुछ लोगों ने बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। वहीं, दो दिन से चल रही बुलडोजर कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

बता दें कि विजय नगर में सोमवार को भी अभियान चलाया गया था। इस दौरान चांदमारी के पास रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर 40 से 50 साल में अवैध रूप से बनाई सैकड़ों झुग्गियों और अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था।

झुग्गियों में संचालित हो रही थीं अवैध गतिविधियां

बताया गया कि इन झुग्गियों में अवैध गतिविधियां भी संचालित हो रही थीं। अपराध को भी बढ़ावा मिल रहा था। झुग्गियों में गांजा और अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें पुलिस और प्रशासन के पास पहुंचती थीं।

अभियान चलाकर की जा रही कार्रवाई

इसके बाद ही अभियान चलाकर यह कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी हाल में अवैध कब्जे को छोड़ा नहीं जाएगा। जहां-जहां लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उन सभी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।

आगरा के लोगों के लिए अच्छी खबर, अब पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं जाना होगा गाजियाबाद; घर बैठे मिलेगी ये सुविधा

गाजियाबाद के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने आगरा के लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया है। अब आगरा के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद नहीं आना पड़ेगा। पासपोर्ट मोबाइल वैन 19 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी और पहली बार इसे सहारनपुर भेजा गया था। अब यह वैन आगरा जाएगी और तीन दिनों तक वहां रहेगी।

गाजियाबाद। पासपोर्ट बनवाने वाले आगरा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें पासपोर्ट बनवाने के लिए गाजियाबाद नहीं आना पड़ेगा। पासपोर्ट मोबाइल वैन आज यानी बुधवार को आगरा जाएगी। मोबाइल वैन में फोटो से लेकर फिंगर प्रिंट सहित सभी जरूरी सत्यापन होगा।

आगरा के बाद अन्य जिले में मोबाइल वैन भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों का उद्देश्य है कि वर्ष 2024 की अपेक्षा 2025 में आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने में अधिक सहूलियत दी जा सके।

पहली बार नौ दिसंबर 2024 को वैन को भेजा गया सहारनपुर

अभी पासपोर्ट बनवाने के लिए जिले के पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया है। वहां पर कई बार लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मोबाइल वैन की सेवा शुरू की गई। पासपोर्ट मोबाइल वैन 19 अक्टूबर 2024 को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय लॉन्च की गई थी।

लॉन्च करने के बाद पहली बार वैन को नौ दिसंबर 2024 को सहारनपुर भेजा गया था। तीन जनवरी तक मोबाइल वैन से सहारनपुर में पासपोर्ट बनाए गए। तभी से वैन कार्यालय में ही खड़ी थी। वैन को आगरा भेजने के लिए उच्चाधिकारियों से अनुमति ली गई। बुधवार से वैन को आगरा भेजा जाएगा। तीन दिन वैन आगरा रहेगी।

तीन दिन के बाद फिर से दोबारा भेजने के संबंध में अधिकारी निर्णय लेंगे। मोबाइल वैन से प्रतिदिन 35 पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया पूरी होगी। वैन में ही फार्म जमा करने के साथ ही सभी कागजों का सत्यापन भी किया जा सकेगा। जिस जिले में पासपोर्ट बनाने वाले अधिक लोग होंगे वहां वैन को पहले भेजा जाएगा।

जब तक उस जिले में पासपोर्ट के आवेदकों की संख्या कम नहीं हो जाती वैन उसी जिले में काम करेगी। अधिकारियों ने बताया कि यदि आवेदक की तरफ से आवेदन के समय किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी जाती है तो पासपोर्ट फंस सकता है।

फिर आवेदक को गाजियाबाद में आना पड़ेगा। आवेदन करते समय से दस्तावेज को सही से चेक कर लें। नाम, जन्मतिथि सहित अन्य तरह की गड़बड़ी मिलती है तो पासपोर्ट बनवाने के लिए चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।

13 जिलों में वैन को भेजने की है प्लानिंग

पासपोर्ट मोबाइल वैन के जरिये लोगों के घर के पास पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंतर्गत 13 जिले गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गौतमबुद्धनगर।

बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, शामली, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, हापुड़ और मथुरा आते हैं। अन्य जिलों में मोबाइल वैन को भेजने की तैयारी की जा रही है। मोबाइल वैन में पासपोर्ट कार्यालय के स्टाफ के साथ ही कंम्प्यूटर, स्कैनर और प्रिंटर आदि उपकरण होंगे।

दुनियाँ के स्वर्ग कहे जाने वाले भारत क़े जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग का चमत्कार - सोनमर्ग टनल व चिनाब रेल ब्रिज तैयार

जम्मू कश्मीर से लिखी दुनियाँ को हैरान करने वाली गाथा - सोनमर्ग टनल व चिनाब रेल ब्रिज की अद्भुत इंजीनियरिंग पर दुनियाँ ने टेका माथा
सोनमर्ग टनल व दुनियाँ के सबसे बड़े रेल ब्रिज चिनाब से जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी, सामाजिक आर्थिक,वाणिज्यिक विकास होगा - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पृथ्वी लोक का स्वर्ग कहे जाने वाला जम्मू कश्मीर भारत का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां हर कोई जाना चाहता है। मेरी भी अभिलाषा है कि मैं एक बार पृथ्वी के इस स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की वादियों में जाऊं परंतु कनेक्टिविटी जलवायु परिवर्तन, मौसम की मार व सबसे बड़ा डर आतंकवाद का था जिसको कंट्रोल करने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 को संसद के दोनों सदनों में पारित कर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से अनुच्छेद 370 रद्द हो गया व भारत की आन बान शान कहे जाने वाले कश्मीर के विकास के लिए नए अध्याय जोड़ने का क्रम शुरू हो गया है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज सोनमर्ग टनल व चिनाब रेल ब्रिज सबके सामने है।हालांकि इन दोनों सबसे बड़ी परियोजनाओं को 10-20 वर्ष पहले से ही शुरू कर दिया गया था परंतु वर्तमान मैं यह दोनों सेवाएं नागरिकों की सेवार्थ तैयार हैं जिनमें से सोनमर्गटनल का शिलान्यास माननीय पीएम ने 13 जनवरी 2025 को किया है, अब शीघ्र ही चिनाब रेल ब्रिज पर भी यात्रियों को लेकर ट्रेन दौड़ने लगेगी, जो शायद इस जनवरी 2025 की एंडिंग तक होने की संभावना है। चूँकि जम्मू कश्मीर से लिखी दुनियाँ की हैरान करने वाली गाथा, सोनमर्ग टनल व चिनाब रेलवे ब्रिज़ की अद्भुत इंजीनियरिंग पर दुनियाँ में टेका माथा, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, दुनियाँ का स्वर्ग कहीं जाने वालेभारत क़े जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग का चमत्कार, सोनमर्ग टनल व चुनाव रेल ब्रिज तैयार।

साथियों बात अगर हम 13 जनवरी 2025 को सोनमर्ग टनल की स्थिति की करें तो, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस टनल को इंजीनियरिंग का चमत्कार और क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताया है। साथ ही कहा कि यह परियोजना न केवल यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएगी, बल्कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच सामाजिक व आर्थिक विकास को भी गति देगी।जेड मार्ड टनल के साथ ज़ोजिला टनल का काम 2028 तक पूरा होगा। यह क्षेत्रीय रक्षा रसद और यातायात को सुगम बनाएगी, इससे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के बीच जुड़ाव और विकास को नई दिशा मिलेगी। टनल के लाभ (1) सोनमर्ग टनल गगनगीर से सोनमर्ग तक निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगी (2) राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर यात्रा की दूरी 49 किमी से घटकर 43 किमी हो जाएगी। (3) वाहनों की गति 30 किमी/घंटा से बढ़कर 70 किमी/घंटा हो जाएगी। (4) यह टनल क्षेत्र के पर्यटन और व्यापार में तेजी लाने में सहायक होगी टनल का रणनीतिक महत्व (5) सोनमर्ग और गगनगीर को जोड़ने वाली यह टनल 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें आपातकालीन स्थिति के लिए 7.5 मीटर चौड़ा समानांतर मार्ग है। ये टनल लद्दाख को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़ने के साथ-साथ देश की रक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय विकास में अहम भूमिका निभाएगी।

साथियों बात अगर हम दिनांक 13 जनवरी 2025 को माननीय पीएम द्वारा इस अवसर पर किए गए 27 मिनट क़े संबोधन को पांच पॉइंट्स में देखें तो (1) सोनमर्ग टनल से लोगों की जिंदगी आसान होगी पीएम ने 27 मिनट के भाषण में कहा, जम्मू-कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। इससे सोनमर्ग के साथ करगिल और लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या बरसात में होने वाली लैंड स्लाइड के कारण रास्ते बंद होने की परेशानी कम होगी। (2) टनल बनाने वाले श्रमिक न डिगे, न घर लौटे पीएम मोदी ने कहा- देश की उन्नति के लिए, जम्मू-कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन को संकट में डालकर काम किया, अपनी जान गंवाई, लेकिन संकल्प से डिगे नहीं। श्रमिक साथी डिगे नहीं, किसी ने घर वापस जाने की बात नहीं की। उन्होंने हर चुनौती को पार करते हुए इस काम को पूरा किया है। जिन 7 साथियों को हमने खोया है, मैं आज सबसे पहले उनका स्मरण करता हूं। (3) सोनमर्ग में टूरिस्ट को पंख लगने वाले हैं, आज भारत तरक्की की नई बुलंदी की तरफ बढ़ चला है। हर देशवासी 2047 तक भारत को डेवलप नेशन बनाने में जुटा है। ये तभी हो सकता है, जब हमारे देश का कोई हिस्सा कोई भी परिवार तरक्की से डेवलपमेंट से पीछे न छूटे। इसके लिए ही हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ पूरे समर्पण से काम कर रही है। इस टनल से सोनमर्ग समेत पूरे इलाके में टूरिज्म को भी नए पंख लगने वाले हैं।(4) लाल चौक पर लोग अब आइसक्रीम खाते हैं पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। चिनाब ब्रिज की इंजीनियरिंग देखकर दुनिया हैरत में है। यहां कुछ दिन पहले पैसेंजर ट्रेन का ट्रायल हुआ। यहां के प्रोजेक्ट्स 42 हजार करोड़ से ज्यादा के हैं। इन पर काम चल रहा है। (5) जम्मू-कश्मीर में गर्मजोशी ऐसी, ठंडक नहीं लगती पीएम नेकहा - ये मौसम, बर्फ, बर्फ की चादर से ढंकी पहाड़ियां देखकर दिल प्रसन्न हो जाता है। यहां आता हूं तो बरसों पहले के दिन याद आने लग जाते हैं। उधर, राज्य के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है जम्मू-कश्मीर के स्टेटहुड का वादा भी पूरा होगा।पीएम ने जेडमोड़ टनलका जायजा लिया। वे खुली जीप में बैठकर टनल देखने गए।पीएम ने जेड मोड़ टनल का जायजा लिया। वे खुली जीप में बैठकर टनल देखने गए।श्रीनगर-लेह हाइवे एनएच-1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन का पीएम ने इनॉगरेशन किया।श्रीनगर- लेह हाइवे एनएच -1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन का पीएम नेइनॉगरेशन किया।जेड मोड़ टनल के इनॉगरेशन के बाद श्रीनगर-लेह हाइवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच एक घंटे की दूरी अब 15 मिनट में पूरी होगी।इसके अलावा गाड़ियों की स्पीड भी 30 किमी/घंटा से बढ़कर 70 किमी/घंटा हो जाएगी। दुर्गम पहाड़ी वाले इस इलाके को क्रॉस करने में पहले 3 से 4 घंटे का समय लगता था। अब यह दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी होगी।उमर अब्दुल्ला बोले- मोदी जी जम्मू-कश्मीर को जल्द राज्य का दर्जा दिलवाएंगे इनॉगरेशन कार्यक्रम में शामिल जम्मू-कश्मीर के सीएम ने कहा- जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए और सबसे बड़ी बात ये रही कि कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई, सत्ता के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं आई। इसका श्रेय आपको (पीएम को),आपके सहयोगियों और भारत के चुनाव आयोग को जाता है। मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द आप (पीएम) राज्य का दर्जा बहाल करने का अपना वादा पूरा करेंगे।

साथियों बात अगर हम 2028 में सोनमर्ग टनल विश्व की सबसे बड़ी टनल होने की करें तो, 2028 में यह एशिया की सबसे लंबी टनल होगीजेड मोड़ टनल के आगे बन रही जोजिला टनल का काम 2028 में पूरा होगा। इसके तैयार होनेके बादही बालटाल (अमरनाथ गुफा), कारगिल और लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी।दोनों टनल के शुरू होने के बाद इसकी कुल लंबाई 12 केएम हो जाएगी। इसमें 2.15 किमी की सर्विस/लिंक रोड भी जुड़ जाएगी। इसके बाद यह एशिया का सबसे लंबी टनल बन जाएगी।फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल एशिया की सबसे लंबी टनल है।इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है।चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक सेना के लिए रसद और हथियार पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बर्फबारी के समय आर्मी पूरी तरह से एयरफोर्स पर निर्भर हो जाती है।दोनों टनल प्रोजेक्ट के पूरे होने से आर्मी कम खर्च में अपना सामान एलएसी तक पहुंचा सकेगी। साथ ही चीन बॉर्डर से पाकिस्तान बॉर्डर तक बटालियन मूव करने में भी आसानी होगी।पिछले साल मजदूरों पर आतंकी हमला भी हुआ था 20 अक्टूबर 2024 को आतंकियों ने टनल के कर्मचरियों पर हमला किया था। दो आतंकी गगनगीर में मजदूरों के कैंप में घुस गए और फायरिंग की थी। इस हमले में टनल का निर्माण कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के 6 मजदूरों सहित 7 लोग मारे गए थे। हमले में एक स्थानीय डॉक्टर की भी मौत हो गई थी।

साथियों बात अगर हम जम्मू कश्मीर में दुनियाँ के सबसे बड़े सबसे ऊंचे पुल चिनाब रेल ब्रिज की करें तो जम्मू- कश्मीर में बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेल ब्रिज पर जल्द ही अब ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। बता दें कि इस ब्रिज का निर्माण उधमपुर- श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया गया है, अब उत्तर रेलवे दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है।असली इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में वर्णित इस पुल के पार्श्व और मध्य भाग में 48 केबल हैं। इसके खंभे पर काम 2017 में शुरू हुआ था और यह संरचना अपनी नींव के स्तर से 191 मीटर ऊपर है।यह कौरी में चेनाब नदी पर बने प्रतिष्ठित आर्च ब्रिज के बाद दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो नदी तल से 359 मीटर ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है तथा पेरिस के एफिल टॉवर से 35 मीटर ऊंचा है। देश की सबसे महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट उधमपुर - श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक को लेकर काम जारी है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिजकश्मीर में बन चुका है। अब जल्द ही इस पर ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो जाएगा।

साथियों बात अगर हम पड़ोसी व विस्तारवादी देश के लिए यह चिंता का विषय होने की करें तो, चिनाब ब्रिज से पाकिस्तान और चीन की चिंता क्यों बढ़ी है? डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके में बना है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक कहा जाता है, जहां अगर चीन का कब्जा हो जाए तो देश दो हिस्सों में टूट सकता है। इसी तरह अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है। इसीलिए इस इलाके में चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए सामरिक तौर पर बेहद खास है। अब हर मौसम में सेना और आम लोग इस हिस्से में ट्रेन या दूसरे वाहनों से जा सकेंगे

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि दुनियाँ के स्वर्ग कहे जाने वाले भारत क़े जम्मू कश्मीर में इंजीनियरिंग का चमत्कार - सोनमर्ग टनल व चिनाब रेल ब्रिज तैयार,जम्मू कश्मीर से लिखी दुनियाँ को हैरान करने वाली गाथा - सोनमर्ग टनल व चिनाब रेल ब्रिज की अद्भुत इंजीनियरिंग पर दुनियाँ ने टेका माथा।सोनमर्ग टनल व दुनियाँ के सबसे बड़े रेल ब्रिज चिनाब से जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी, सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक विकास होगा

हुंडई लाएगी टोयोटा इनोवा की टक्कर की गाड़ी, ऑटो एक्सपो 2025 में करेगी शोकेस

परिवहन विशेष न्यूज

हुंडई की नई कारें 2025ऑटो एक्सपो 2025 में हुंडई अपनी नई MPV को भारत में पेश कर सकती है। यह Hyundai Staria हो सकती है। यह ग्लोबल बाजार में कई प्रीमियम फीचर्स और केबिन के साथ आती है। इसे कंपनी इसके 7 सीटर को भारत में ला सकती है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के पहले दिन पेश होने की उम्मीद है।

नई दिल्ली। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में Hyundai अपनी क्रेटा इलेक्ट्रिक को लॉन्च करने जा रही है। इसके साथ ही ऑटोमेकर ऑटो एक्सपो 2025 में Hyundai Staria को भी पेश करेगी। यह हुंडई की लग्जरी MPV कार है। इसे कंपनी 17 जनवरी 2025 को पेश करेगी। इसे हाल में मुंबई सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट भी किया जा चुका है। आइए जानते हैं कि Hyundai Staria में क्या कुछ खास रहने वाला है।

6-सिलेंडर इंजन मिलेगा

भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 के दौरान पेश होने जा रही Hyundai Staria में माइल्ड-हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। इसमें 3.5-लीटर पेट्रोल वी-टाइप 6-सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलेगा। यह इंजन 290PS की पावर और 338Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसे भारत में टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है।

8 कलर ऑप्शन मिलेंगे

यह ग्लोबल स्पेक में 8 कलर ऑप्शन में पेश की जाती है। भारत में भी इतने ही कलर ऑप्शन में इसे पेश किया जा सकता है। इसमें आपको स्मार्ट दरवाजे देखने के लिए मिलेंगे, जो आपने आप ही खुल जाएंगे। इसके पीछे की सीटों को मोड़कर आप एक्सट्रा जगह बना सकेंगे। इसके साथ ही इसमें, बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम, स्मार्ट पावर टेलगेट (ऑटो-क्लोज फंक्शन के साथ), घूमने वाली सीट, प्रीमियम रिलैक्सिंग सीट जैसे फीचर्स मिलेंगी।

ADAS के ये फीचर्स मिलेंगे

Hyundai Staria में ADAS फीचर्स भी

देखने के लिए मिलेंगे। ADAS फीचर्स के रूप में इसमें फॉरवर्ड कोलिजन-एवॉइडेंस असिस्ट (FCA), लेन कीपिंग असिस्ट (LKA), ब्लाइंड-स्पॉट टक्कर-निवारण सहायता (BCA), सुरक्षित निकास सहायता (SEA), स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल (एससीसी), लेन फॉलोइंग असिस्ट (LFA), रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक टक्कर-निवारण सहायता (RCCA) जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इंटीरियर

Hyundai Staria में फुल एलईडी हेडलैम्प, रंगीन पीतल क्रोम बम्पर, पहली पंक्ति में डबल-लेमिनेटेड ध्वनिरोधी ग्लास टच-टाइप बाहरी दरवाज़े का हैंडल (पहली पंक्ति) शिफ्ट-बाय-वायर स्वचालित ट्रांसमिशन एलईडी हेडलैम्प (वैकल्पिक) दोहरी सनरूफ (केवल वैकल्पिक_वैगन) फ्लश ग्लास (वैकल्पिक) पहली पंक्ति वेंटिलेटेड सीटें, पहली पंक्ति डबल-लेमिनेटेड साउंड प्रूफ ग्लास, शिफ्ट-बाय-वायर स्वचालित ट्रांसमिशन, 8 इंच डिस्प्ले ऑडियो जैसे प्रीमियम फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे।

मारुति इको ने पूरा किया 15 साल का सफर, 12.5 लाख यूनिट्स की हुई बिक्री, कीमत 5.32 लाख रुपये से शुरू

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति इको 15 साल मारुति सुजुकी की ओर से कई बेहतरीन वाहनों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें वैन सेगमेंट में Maruti Eeco को लाया जाता है। इस गाड़ी ने देश में 15 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान कितनी यूनिट्स की बिक्री हुई है। किस तरह के फीचर्स और कीमत के साथ इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माताओं में से एक Maruti Suzuki की ओर से कई सेगमेंट में कारों की बिक्री की जाती है। कंपनी की ओर से Van सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली Maruti Eeco ने देश में 15 साल का सफर पूरा कर लिया है। इस दौरान गाड़ी की कितनी यूनिट्स की बिक्री हुई है। किस तरह के फीचर्स, इंजन के साथ इसे लाया जाता है। किस कीमत पर गाड़ी को खरीदा जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Maruti Eeco ने पूरे किए 15 साल

मारुति सुजुकी की ओर से वैन सेगमेंट में ऑफर की जाने वाली गाड़ी Maruti Eeco ने 15 साल का सफर (Maruti Eeco 15 years milestone) पूरा कर लिया है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी को 2010 में लॉन्च किया गया था। इस दौरान इसमें कई तरह के बदलाव भी किए गए, जिनको पसंद भी किया गया है।

कितनी हुई बिक्री

कंपनी से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 15 सालों के दौरान इस गाड़ी की काफी मांग रही है। आंकड़ों के मुताबिक इसे 15 साल में 12.5 लाख (Maruti Eeco sales) लोगों ने खरीदा है। कंपनी की ओर से इसे पेट्रोल के साथ ही सीएनजी ईंधन के विकल्प में भी लाया जाता है। गाड़ी की कुल बिक्री में सीएनजी की 43 फीसदी की हिस्सेदारी है।

कितना दमदार इंजन

Maruti Eeco में कंपनी की ओर से 1.2 लीटर की क्षमता का K-सीरीज इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 80.7 पीएस की पावर और 104.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। वहीं इसके सीएनजी वर्जन में भी इसी इंजन का उपयोग किया जाता है जिससे इसे 71.6 पीएस की पावर और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है।

कैसे हैं फीचर्स

Maruti Eeco में कंपनी की ओर से एसी, हीटर, रिक्लाइनिंग फ्रंट सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल इंटीरियर, इमोबिलाइजर, एबीएस, ईबीडी, एयरबैग, स्पीड अलर्ट सिस्टम, ईएसपी, पार्किंग सेंसर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, सीट बेल्ट रिमाइंडर जैसे फीचर्स दिए जाते हैं।

कितनी है कीमत

Maruti Eeco को कुल 13 वेरिएंट्स के साथ ही पांच और सात सीटों के विकल्प के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसे सामान्य गाड़ी के अलावा कार्गो, टूर और एंबुलेंस के विकल्प में भी लाया जाता है। Maruti Eeco की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 5.32 लाख रुपये है और इसके टॉप वेरिएंट को 6.58 लाख रुपये (Maruti Eeco price) की एक्स शोरूम कीमत पर लाया जाता है।

एमजी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में की बढ़ोतरी, कोमेट से लेकर जेडएस ईवी तक के बढ़े दाम

परिवहन विशेष न्यूज

एमजी कारों की कीमत में बढ़ोतरी जनवरी 2025 में एमजी मोटर्स ने अपने मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। MG ZS EV की कीमतों में 1.20 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है तो वही MG Comet में 19 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही MG Astor की कीमतों में 49 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

नई दिल्ली। जनवरी 2025 में MG Motor ने अपनी गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी की है। MG ने अपनी ICE के साथ ही इलेक्ट्रिक कार की भी बढ़ोतरी की है। कंपनी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में 12 हजार रुपये लेकर 50 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं कि MG Motor की गाड़ियों की कितनी कीमत बढ़ी है।

MG ZS EV

MG Motor ने अपनी इलेक्ट्रिक कार ZS EV की कीमतों में 1.20 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसके बेस वेरिएंट में कीमत को नहीं बढ़ाया गया है।

Excite Pro की कीमत में 49,800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

Exclusive Plus वेरिएंट की कीमत 92,000 रुपये बढ़े है।

Exclusive Plus Dual Tone की कीमत 91,000 रुपये बढ़ी है।

Essence वेरिएंट की कीमत में 1,21,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

Essence Dual Tone की कीमत 1,20,000 रुपये बढ़ी है।

MG Astor

MG Motor ने अपनी Astor की कीमत में 49 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है। इसके भी बेस वेरिएंट में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई है।

1.5L सामान्य पेट्रोल-मैनुअल

Shine वेरिएंट की कीमत में 12,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई बै।

Select वेरिएंट की कीमत 13,000 रुपये बढ़ी है।

Select Black Storm की कीमत भी 13 हजार रुपये बढ़ी है।

Sharp Pro की कीमत में 21,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

Sharp Pro 100Y कीमत 45,000 रुपये बढ़ाई गई है।

ऑटोमेटिक

Select वेरिएंट की कीमत में 14,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

Select Black Storm कीमत भी 14,000 रुपये तक बढ़ी है।

Sharp Pro की कीमत में 23,000 रुपये तक बढ़ोतरी हुई है।

Sharp Pro 100Y की कीमत 49,000 रुपये तक बढ़ी है।

Savvy Pro की कीमत में 24,000 रुपये तक बढ़ाई गई है।

MG Comet

MG Motor की इलेक्ट्रिक कार Comet की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है।

Excite की कीमत में 12,000 रुपये में बढ़ोतरी हुई है।

Excite FC की कीमत 17,000 रुपये बढ़ाई गई है।

Exclusive की कीमत में 14,000 रुपये बढ़ोतरी हुई है।

Exclusive FC की कीमत 19,000 रुपये बढ़ी है।

100YR Edition की कीमत भी

किआ EV6 फेसलिफ्ट होगी ऑटो एक्सपो 2025 में पेश, सोशल मीडिया पर जारी हुआ नया टीजर

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में बेहतरीन वाहनों की बिक्री की जाती है। कंपनी की ओर से Auto Expo 2025 में भी कई नई कारों को पेश करने की तैयारी की जा रही है। हाल में ही Kia ने अपनी प्रीमियम Electric SUV के तौर पर ऑफर की जाने वाली Kia EV6 का नया टीजर जारी किया है। इसमें क्या जानकारी दी जा रही है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जारी हुआ टीजर

किआ इंडिया की ओर से जल्द ही प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Kia EV6 के Facelift को लाने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से एसयूवी को पेश करने से पहले टीजर वीडियो को जारी (Kia EV6 new teaser launch) किया गया है।

क्या मिली जानकारी

कंपनी की ओर से सोशल मीडिया पर जारी किए गए टीजर के मुताबिक Kia EV6 Facelift में ज्यादातर बदलाव कॉस्मैटिक होंगे। इसके मूल डिजाइन में किसी भी तरह का बड़ा बदलाव नहीं किया जाएगा। टीजर के मुताबिक नई Kia EV6 में कंपनी कनेक्टिड एलईडी लाइट्स को देगी। इसके अलावा इसमें पहले की ही तरह सिंगल पेन सनरूफ दिया जाएगा। साथ ही कुछ नए फीचर्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा।

कितनी होगी रेंज

कंपनी की ओर से Kia EV6 Facelift की बैटरी और मोटर में ज्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा वर्जन की तरह ही 77.4 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जाएगा। जिससे इसे फुल चार्ज में 700 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। इसमें परमानेंट मेग्नेट सिंकोरियस मोटर को दिया जाएगा जिससे 229 पीएस की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा।

कब होगी पेश

किआ की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Kia EV6 के Facelift वर्जन को कंपनी की ओर से Bharat Mobility 2025 के तहत होने वाले Auto Expo 2025 में पेश (Kia EV6 Facelift Auto Expo 2025) किया जाएगा। जिसके कुछ समय बाद इसे लॉन्च किया जाएगा।

कितनी होगी कीमत

कंपनी की ओर से इसके मौजूदा वर्जन को GT-Line और LT-Line AWD वेरिएंट के विकल्प में लाया जाता है। जिसकी एक्स शोरूम कीमत 60.97 लाख रुपये से शुरू होती है। ऐसे में फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत में ज्यादा बदलाव होने की संभावना कम है।

किनसे होता है मुकाबला

Kia EV6 को प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Ioniq5, Lexus NX, BMW i4, Volvo XC40 Recharge जैसी एसयूवी के साथ होता है।

नई हीरो डेस्टिनी 125 हुई लॉन्च; नया डिजाइन, कलर समेत मिले एडवांस फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो डेस्क नई दिल्ली। नई 2024 Hero Destini 125 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है। इसे नया डिजाइन समेत एडवांस फीचर्स से लैस किया गया है। इसके साथ ही इसे नए कलर भी दिए गए हैं। नई हीरो डेस्टिनी 125 को तीन वेरिएंट VX ZX और ZX+ में लाया गया है। इसके टॉप वेरिएंट ZX+ में स्मार्टफोन कनेक्टिवीटी फीचर दिया गया है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार के लिए नई Hero Destini 125 को लॉन्च कर दिया गया है। इसे पिछले साल पेश किया गया था। हीरो मोटोकॉर्प का यह नया और मॉडर्न 125cc स्कूटर है। नई हीरो डेस्टिनी 125 को स्मार्टफोन कनेक्टिविटी समेत कई एडवांस फीचर्स के साथ लाया गया है। इसे तीन ट्रिम में पेश किया गया है। आइए जानते हैं कि 2024 Hero Destini 125 को किन फीचर्स के साथ लेकर आया गया है।

इंजन

नई Hero Destini 125 में वहीं पुराने 124.6cc एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलिंडर का इस्तेमाल किया गया है, जो 9 PS की पावर और 10.4 Nm टॉर्क जनरेट करता है। हीरो ने इसे अपडेट करने के साथ नया CVT (कंटीन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन) दिया गया है।

फीचर्स

नई डेस्टिनी 125 स्कूटर को नए डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें H-इन्सिग्निया के साथ एक स्टाइलिश LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है। इसमें इल्यूमिनेटेड स्टार्ट बटन के साथ टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसमें आगे की तरफ 190mm डिस्क ब्रेक, बेहतर 12-इंच के आगे और पीछे के पहिये, चौड़े पीछे के टायर के साथ हीरो का i3S स्टॉप/स्टार्ट फ़ीचर को शामिल किया गया है।

कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि नई डेस्टिनी एक लीटर पेट्रोल में 59 किलोमीटर तक का माइलेज देगी। इसके टॉप-स्पेक ZX+ ट्रिम में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन दिया गया है।

कीमत

नई Hero Destini 125 को तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो VX, ZX और ZX+ है। VX ट्रिम को तीन कलर ऑप्शन इटरनल व्हाइट, रीगल ब्लैक और ग्रूवी रेड में लाया गया है। इसके ZX ट्रिम को दो कलर ऑप्शन कॉस्मिक ब्लू और मस्टीक मैजेंटा में लाया गया है। वहीं, इसके ZX+ ट्रिम को इटरनल व्हाइट और रीगल ब्लैक कलर के साथ लॉन्च किया गया है। इसके टॉप वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

VX की एक्स-शोरूम कीमत 80,450 रुपये।

ZX की एक्स-शोरूम कीमत 89,300 रुपये।

ZX+ की एक्स-शोरूम कीमत 90,300 रुपये।

भारतीय बाजार में 125 cc की स्कूटर सेगमेंट में नई Hero Destini 125 का मुकाबला Suzuki Access 125, Yamaha Fascino 125, Activa 125 और TVS Jupiter 125 से देखने के लिए मिलेगा।

ऑटो एक्सपो 2025 में स्विच मोबिलिटी कर रही दो कमर्शियल वाहनों को पेश करने की तैयारी, जान लें क्या होगा खास

परिवहन विशेष न्यूज

ऑटो एक्सपो 2025 अशोक लीलैंड के स्वामित्व वाली ब्रिटिश कमर्शियल वाहन निर्माता Switch Mobility की ओर से Bharat Mobility 2025 के दौरान दो नए कमर्शियल वाहनों को पेश करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से किस सेगमेंट में कितनी रेंज और क्षमता के साथ इन वाहनों को पेश करने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। ब्रिटेन की इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन निर्माता Switch Mobility की ओर से Bharat Mobility 2025 के तहत होने वाले Auto expo 2025 में नए वाहनों को पेश करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से इस दौरान किस सेगमेंट में कितनी क्षमता के साथ किन दो वाहनों को लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Switch Mobility करेगी दो नए कमर्शियल वाहनों को पेश

Ashok Ley land के स्वामित्व वाली ब्रिटिश इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन निर्माता Switch Mobility की ओर से भारत में जल्द ही दो नए इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को पेश करने की तैयारी की जा रही है। कंपनी की ओर से इन दोनों वाहनों को Bharat Mobility 2025 के तहत होने वाले Auto Expo 2025 में पेश किया जाएगा।

टीजर जारी कर दी जानकारी

कंपनी की ओर से टीजर फोटो को जारी कर यह जानकारी दी गई है। टीजर में दो इलेक्ट्रिक वाहनों की झलक को दिखाया गया है। इसके साथ ही A New Leap in Electric Mobility लिखा गया है। साथ में 17 से 22 जनवरी 2025 की तारीख को भी लिखा गया है।

किस तरह के होंगे वाहन

कंपनी की ओर से अभी सिर्फ एक टीजर फोटो को जारी कर नए इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों को लाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा अभी और किसी भी तरह की जानकारी को नहीं दिया गया है। लेकिन फोटो के मुताबिक आने वाले दोनों इलेक्ट्रिक वाहनों को ट्रक सेगमेंट में लाया जाएगा। दोनों ही नए वाहनों को कंपनी अलग-अलग सेगमेंट में लाएगी। इनमें से एक को IeV5 नाम से लाया जा सकता है और दूसरे वाहन को IeV6 नाम दिया जा सकता है। लेकिन इसकी जानकारी लॉन्च के समय ही मिल पाएगी।

कितनी होगी रेंज और क्षमता

कम क्षमता वाले नए इलेक्ट्रिक ट्रक को कंपनी की ओर से 2.10 टन से ज्यादा की पेलोड क्षमता के साथ लाया जा सकता है। इसमें कंपनी की ओर से करीब 160 किलोमीटर तक की रेंज दी जा सकती है। इसमें करीब 40 kWh की क्षमता की बैटरी को दिया जा सकता है और कई नए फीचर्स को भी ऑफर किया जा सकता है।

इसके अलावा ज्यादा क्षमता वाले वाहन के तौर पर दूसरे इलेक्ट्रिक ट्रक को ढाई टन से ज्यादा की पेलोड क्षमता और करीब 200 किलोमीटर के आस-पास की रेंज के साथ लाया जा सकता है। इसमें 60 kWh की क्षमता की बैटरी के साथ कई बेहतरीन फीचर्स को दिया जा सकता है।

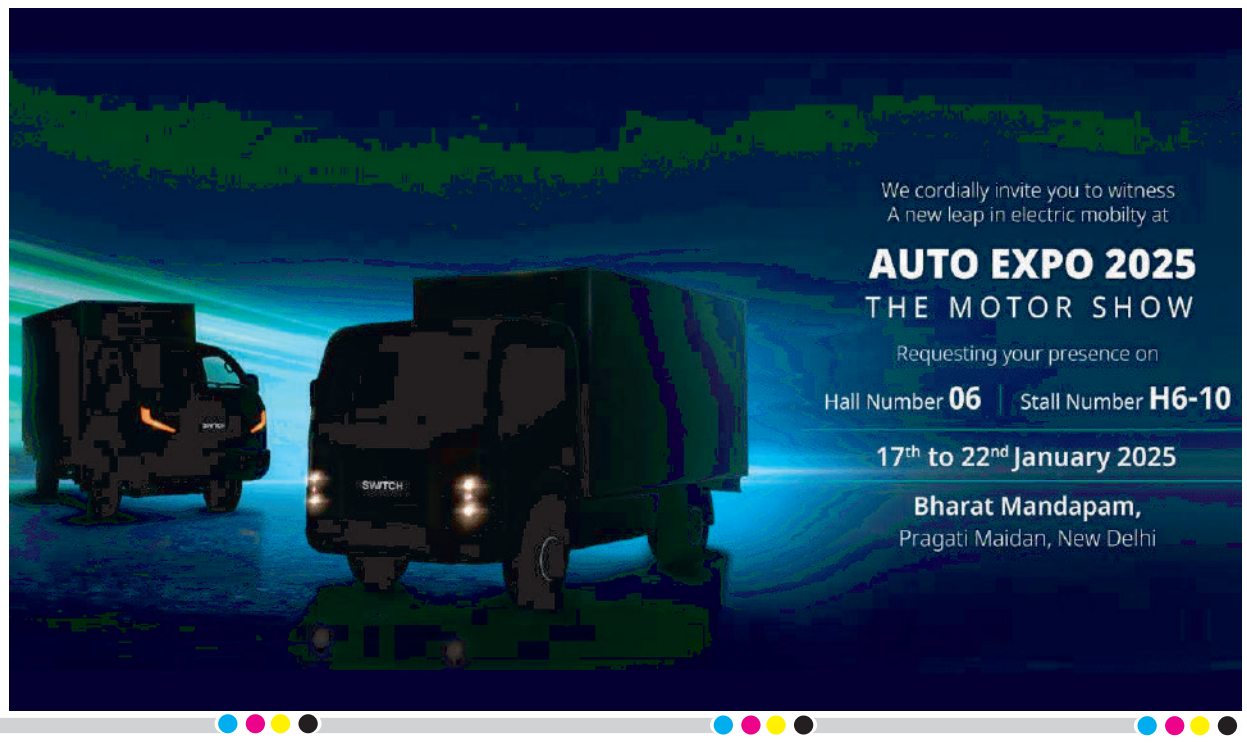

मध्यम आय के घेरे में उलझा विश्व

विजय गर्ग

विश्व बैंक द्वारा जारी विश्व विकास रपट 2024 वैश्विक अर्थिक परिदृश्य में मध्यम आय जाल की चिंता तथा इससे निकलने के उपाय सुझाती है। आर्थिक विकास के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद पिछले सैंतीस वर्षों के बाद मात्र चौंतीस देशों को मध्यम आय जाल बाहर निकलने में कामयाबी मिल सकी है। आज दुनिया भर की लगभग छह अरब आबादी वाले 108 देश मध्यम आय जाल नकी जकड़ में हैं, जहां आर्थिक विकास दर अपेक्षाकृत कमजोर है। वहां मंदी बार-बार पलटती रही है। बढ़ती वैश्विक भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के कारण तीव्र आर्थिक विकास में दिक्कतें हैं। इसलिए मध्यम-आय देशों को विशेष प्रयास करने होंगे। विकसित भारत की संकल्पना के सम्मुख भी मध्यम- आय जाल चुनौती है, जिससे भारत को बचना होगा।

₹विश्व बैंक, वर्ष 1987 से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के चार वर्गों उच्च आय, उच्च-मध्यम आय, निम्न मध्यम आय तथा निम्न आय में विभाजन करता रहा है। सैंतीस वर्षों बाद, उच्च आय वाले देशों की संख्या 41 से बढ़ कर 86 गई, जिनकी वैश्विक आबादी तथा जीडीपी में हिस्सेदारी क्रमशः 16 और 60 फीसद है। निम्न आय वाले देशों की संख्या 49 से कर 26 रह जाने के बाद वैश्विक आबादी तथा जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी क्रमशः नौ फीसद और 0.6 फीसद रह गई। दुनिया की लगभग तीन चौथाई आबादी तथा जीडीपी में 38 फीसद हिस्सा रखने वाले मध्यम आय देशों की संख्या 74 से बढ़ कर 108 हो गई। मध्य- आय देशों में 1970 के दशक से निरंतर प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के दसवें हिस्से से भी कम रही है। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 11 फीसद तक पहुंचने के बाद व्यवस्थागत दिक्कतों के कारण मध्यम आय जाल में फंस जाती है।

निम्न आय देश निवेश को निर्देशित कर तीव्र विकास दर हासिल करते हैं। मध्यम-आय अर्थव्यवस्था वाले देशों में बढ़ते ऋणभार बढ़ता संरक्षणवाद, भू- -राजनीतिक तनाव, विदेशी व्यापार तथा निवेश में गिरावट जैसे कारण सुस्त आय वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक दुश्वारियां बढ़ा

रहे हैं। निजी निवेश के साथ-साथ सार्वजनिक निवेश भी घटे हैं, लोकलुभावन वादों वाली सरकारों के सामने आर्थिक गुंजाइशें भी कम हैं। मगर मध्यम आय देश आज भी भी निवेश बढ़ाने की पुरानी तथा परंपरागत रणनीतियों पर ही भरोसा बनाए हुए हैं। पूंजी निवेश विकास रणनीति निम्न आय देशों की अपेक्षा मध्यम आय देशों में कम ही कामयाब हैं।

मध्यम आय देशों में उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की महत्त्वाकांक्षा स्वाभाविक है। मध्यम-आय जाल से बचने के लिए विश्व विकास रपट तीन कारकों की पहचान करती है- निवेश, आधुनिक तकनीक का प्रसार तथा नवाचार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं निवेश प्रेरित नीतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं को उच्च आय स्तर प्राप्त र उसे बरकरार रखने एवं आर्थिक संरचनाएं विकसित करने के लिए विकास क्रम के आधार पर उत्तरोत्तर दो मिश्रित नीति संक्रमणों से गुजरना होगा।

भारत जैसे मध्यम आय देशों को संरचनात्मक दक्षता के सतही तथा परंपरागत उपायों जैसे उद्यम आकार, आय असमानता तथा ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा पूंजी, श्रम तथा ऊर्जा के बेहतर उपयोग के साथ दक्षता पर भरोसा करना होगा। इनको मूल्य संवर्द्धन, सामाजिक आर्थिक गतिशीलता और कम कार्बन उत्सर्जन तकनीक पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

मध्यम आय देशों में बड़े निगम, सार्वजनिक उद्यम और प्रभावी उद्यमिता उपयोगी हो सकते हैं। पूंजी के कुशल उपयोग के लिए लघु तथा मध्यम उद्यमों के सम्मुख बाधाएं पैदा करने तथा बड़े उद्यमों को परेशान करने से बचना होगा। उद्यम प्रबंधन को आधुनिक तथा बाजार से जोड़ते हुए अलाभकर उद्यमों से निजात पाना भी जरूरी है।

मध्यम आय जाल से बाहर आने में पूर्व तथा नवस्थापित दोनों ही उद्यम मददगार हो सकते हैं। पूर्व स्थापित उद्यम पैमाना लाते हैं, जो किसी देश की तकनीकी क्षमताओं का वैश्विक प्रसार एवं विस्तार करते हैं। नवाचार जरिए पुरानी व्यवस्थाओं, उद्यमों, नौकरियों, प्रौद्योगिकी, निजी अनुबंधों, नीतियों और सार्वजनिक संस्थानों का प्रतिस्थापन जरूरी है। आमतौर पर सार्वजनिक उद्यम यथास्थिति बनाए रखने, कम कार्बन उत्सर्जन प्रतिस्पर्धा से बचने का प्रयास करते हैं। अनेक अर्थव्यवस्थाएं कम कार्बन प्रौद्योगिकी उत्पादों को प्रोत्साहित कर रही हैं। संस्थागत तौर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, मध्यम-आय देश लोगों का समर्थन सुनिश्चित कर बाजार शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। विदेशी व्यापार, निवेश और प्रतिभा सम्मान तकनीक उन्नयन में मदद करता है। मध्यम-आय अर्थव्यवस्थाओं को विकास और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करना होता है। मध्यम-आय देश-निवेश के साथ- साथ नवाचार को बढ़ा कर जलवायु और ऊर्जा संकट का लाभ उठाने के लिए 'डीकार्बोनाइजेशन' तकनीक का समर्थन कर सकते हैं। कार्बन उत्सर्जन को घटाने के लिए मध्यम आय देश प्रभावी कीमत तंत्र के जरिए उत्तरोत्तर कम कार्बन ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। सस्ती तथा विश्वसनीय ऊर्जा तेज आर्थिक विकास की बुनियाद है, पर ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन उत्सर्जन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

भारत को वहां तक पहुंचने में लगभग पचहत्तर वर्ष लग जाएंगे। फिर भी, विश्व विकास रपट विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की कोशिशों में भारत को सतर्क करती है। भारत को अभी उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की लंबी यात्रा तय करनी है। यहां आर्थिक विकास की जबरदस्त संभावनाएं हैं। भारत जनांकिकी लाभांश की स्थिति में है, ऊर्जा दक्षता और कम कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य निर्धारित हैं, कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में भारत में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है, हरित तकनीक प्राथमिकता बनी है, डिजिटल सार्वजनिक अधोसंरचना निर्माण तेज है। नीतिगत स्पष्टता बढ़ी है, शिक्षा एवं कौशल विकास, डिजिटल इंडिया तथा मेक इन इंडिया पर जोर है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ- साथ नवाचार भी बढ़ा है। साथ ही चुनौतियां भी नए कलेवर में सामने हैं। भारत में सामाजिक-राजनीतिक संस्थान एवं व्यवस्थाएं बदलाव पर हठधर्मिता छोड़ने को तत्पर नहीं नहीं हैं। गरीबी, बेरोजगारी तथा सामाजिक-आर्थिक असमानता का सिलसिला बरक बरकरार है। राजनीतिक संस्थाओं को लोकलुभावन के जरिए सत्ता हथियाने से गुरेज नहीं है।

उपायों के भारत को निम्न मध्यम आय से उच्च मध्यम आय तक का लंबा सफर तय तय करने के लिए विकास केंद्रित नजरिया रखना होगा। भारत को विश्व विकास। रपट से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। अभी तो भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं। सामाजिक-आर्थिक बदलाव की संभावनाएं स्पष्ट हैं। भारत को मध्यम- आय जाल से घबराने के बजाय मजबूत संकल्पों तथा तय लक्ष्यों के साथ विकसित भारत की ओर रफ्तार बढ़ाना है।

घटते छात्र, बढ़ते स्कूल

विजय गर्ग

₹घटते छात्र, बढ़ते स्कूल₹ एक गंभीर सामाजिक और शैक्षिक मुद्दा है, जो शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या संरचना, और संसाधनों के असमान वितरण से जुड़ा है। इस समस्या को समझने के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जा सकता है:

1. घटते छात्र

जनसंख्या वृद्धि में कमी: कई देशों और क्षेत्रों में जन्म दर में गिरावट के कारण स्कूलों में नामांकन कम हो रहे हैं।

माइग्रेशन: ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के कारण ग्रामीण स्कूलों में छात्रों की संख्या कम हो जाती है।

गुणवत्ता का अभाव: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में गिरावट के कारण माता-पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं।

डिजिटल शिक्षा का बढ़ना: ऑनलाइन शिक्षा और होम-स्कूलिंग की बढ़ती लोकप्रियता ने भी छात्रों की संख्या पर असर डाला है।

2. बढ़ते स्कूल

निजीकरण का प्रभाव: प्राइवेट स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं।

नीतिगत परिवर्तन: सरकारें शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए अधिक स्कूल खोल रही हैं, लेकिन जनसंख्या गिरावट या छात्र नामांकन में कमी को नजरअंदाज कर रही हैं।

शहरीकरण और विशेष स्कूल: बड़े शहरों में विशेष पाठ्यक्रम और सुविधाओं वाले स्कूलों की मांग बढ़ रही है।

3. प्रभाव

संसाधनों की बर्बादी: कम छात्रों के साथ अधिक स्कूल होने से संसाधनों का असमान उपयोग होता है।

गुणवत्ता में गिरावट: शिक्षक और प्रशासन पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे गुणवत्ता में कमी आ सकती है।

सामाजिक असंतुलन: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के अवसरों की असमानता बढ़ती है।

4. समाधान के उपाय

सुनियोजित स्कूल निर्माण: जनसंख्या और आवश्यकता के आधार पर स्कूलों का निर्माण होना चाहिए।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाकर छात्रों को आकर्षित करना।

संसाधनों का कुशल प्रबंधन: संसाधनों का पुनर्वितरण और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना।

नवीनतम तकनीक का उपयोग: डिजिटल और पारंपरिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाना।

इस समस्या का समाधान सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक स्तर पर सामूहिक प्रयासों से ही संभव है।

आईआईटी प्लास्टिसाइज़र को ख़राब करने के लिए जीवाणु एंजाइमों का उपयोग करता है

विजय गर्ग

प्लास्टिक के अलावा, पर्यावरण में कार्सिनोजेनिक प्लास्टिसाइज़र की मात्रा चिंताजनक दर से बढ़ रही है। प्लास्टिसाइज़र लचीलेपन और चमक को बढ़ाने के लिए प्लास्टिक और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में मिलाए जाने वाले रसायन हैं और आमतौर पर बच्चों के खिलौने, शैंपू, साबुन और खाद्य कंटेनर जैसी वस्तुओं में पाए जाते हैं। प्लास्टिसाइज़र त्वचा के माध्यम से अवशोषित हो सकते हैं, जिससे वे मानव स्वास्थ्य के लिए सीधा खतरा बन जाते हैं। आईआईटी रूड़की के बायोसाइंसेज और बायोइंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. प्रवींद्र कुमार के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने डायथाइल हेक्सिल फोथलेट (डीईएचपी) प्लास्टिसाइज़र को तोड़ने के लिए मिट्टी के बैक्टीरिया सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस द्वारा उत्पादित एंजाइमेस्टरेज़ एंजाइम का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। जबकि एक चीनी टीम ने इस एंजाइम को कम आणविक भार फ़ेथलेट डायस्टर प्लास्टिसाइज़र को ख़राब करने की विशेषता बताई थी, जिसे कई रिपोर्ट किए गए एस्टरेज़ एंजाइमों द्वारा ख़राब किया जा सकता है, आईआईटी रूड़की टीम ने इसकी वास्तविक क्षमता की पहचान की है और इसका उपयोग उच्च आणविक भार फ़ेथलेट प्लास्टिसाइज़र को ख़राब करने के लिए किया है। शोध को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश द्वारा वित्त पोषित किया गया था और परिणाम हाल ही में जर्नल स्ट्रक्चर में प्रकाशित हुए थे। समूह ने यह भी पता लगाया है कि एस्टरेज़ एंजाइम प्लास्टिक में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपाइलीन के समान अणुओं को बांध सकता है, जिससे यह दूषित जल स्रोतों से पॉलीप्रोपाइलीन निकालने का एक संभावित उपकरण बन जाता है। एस्टरेज़ एंजाइम को एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग करके संरचनात्मक रूप से चित्रित किया गया था। आईआईटी रूड़की की शैलजा वर्मा और पेपर की पहली लेखिका कहती हैं, ₹इससे एंजाइमों की सक्रिय साइटों की पहचान करने और विस्तृत तंत्र को समझने में मदद मिली जिसके द्वारा यह एंजाइम डीईएचपी प्लास्टिसाइज़र को ख़राब करता है।₹ प्लास्टिसाइज़र को ख़राब करने के लिए एंजाइम की दक्षता को समझने के लिए अन्य परिष्कृत जैव रासायनिक और जैव-भौतिकीय दृष्टिकोणों का भी उपयोग किया गया था। एस्टरेज़ एंजाइम लगभग एक महीने तक सक्रिय रहता है और महत्वपूर्ण दक्षता के साथ DEHP प्लास्टिसाइज़र के क्षरण को उत्प्रेरित करता है। इस एंजाइम के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए, शोधकर्ताओं ने EstS1 एस्टरेज़ एंजाइम के जीन को इकोलिबैक्टेरिया में क्लोन किया और एरोबिक संस्कृति के माध्यम से बड़े पैमाने पर एंजाइम का उत्पादन किया गया। एंजाइम DEHP प्लास्टिसाइज़र को तोड़ देता है दो उत्पादों में - मोनो- (2-एथिलहेक्सिल) फ़ेथलेट (एमईएचपी) और 2-एथिल हेक्सानॉल। प्रो. कुमार के अनुसार, यह एस्टरेज़ एंजाइम, उनके समूह द्वारा पहले पहचाने गए अन्य एंजाइमों के साथ उच्च आणविक भार फ़ेथलेट प्लास्टिसाइज़र को पानी और कार्बनडाइऑक्साइड में परिवर्तित कर सकता है। और यहीं पर आईआईटी रूड़की की टीम को बढ़त मिलती दिख रही है। डॉ. कुमार कहते हैं, ₹हमारे शोध के नतीजे सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देते हैं जो प्लास्टिक और प्लास्टिसाइज़र मुक्त भविष्य की दिशा में एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है।₹ इस कार्य में शामिल अन्य शोधकर्ताओं में श्वेता चौधरी, कांबले अमिथ कुमार, जय कृष्ण महतो, इशानी मिश्रा, डॉ. अश्विनी कुमार शर्मा, डॉ. शैली तोमर, डॉ. देबब्रत सरकार और डॉ. जितिन सिंगला शामिल हैं। 2017 में, टीम ने एक अन्य मृदा जीवाणु कोमामोनस टेस्टोस्टेरोनी को अलग किया जो DEHP क्षरण द्वारा उत्पादित फ़ेथलेट्स को कार्बनडाइऑक्साइड और पानी में तोड़ देता है। प्रयोगशाला में, शोधकर्ताओं ने अनुक्रम में एंजाइमों का उपयोग किया, पहले एस्टरेज़ एंजाइम का उपयोग करके DEHP को MEHP और 2-एथिल हेक्सानॉल में तोड़ दिया, जिसे बाद में दूसरे एंजाइम का उपयोग करके फ़ेथलेट में अपघटित कर दिया गया। फिर फ़ेथलेट को तीसरे एंजाइम (फ़थलेट डाइऑक्सीजिनेज़) का उपयोग करके मध्यवर्ती यौगिकों में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद मध्यवर्ती यौगिक का उत्पादन हुआस्टेप को एंजाइम फ़ेथलेट डिकार्बोक्सिलेज़ द्वारा प्रोटोकैच्यूएट में परिवर्तित किया जाता है। एक बार जब प्रोटोकैच्यूएट का उत्पादन हो जाता है, तो बैक्टीरिया का ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड चक्र इसे कार्बनडाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है। जबकि DEHP को MEHP और 2-एथिल हेक्सानॉल में तोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला एस्टरेज़ एंजाइम सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया से है, अनुक्रम में उपयोग किए जाने वाले तीन अन्य एंजाइम कोमामोनस टेस्टोस्टेरोनी बैक्टीरिया से हैं। सुश्री वर्मा कहती हैं, ₹प्रयोगशाला में, हमने डीईएचपी को पानी और कार्बनडाइऑक्साइड में तोड़ने के क्रम में एंजाइमों का उपयोग करने की कोशिश की है।₹ ₹अब हम डीईएचपी प्लास्टिसाइज़र को सीधे पानी और कार्बनडाइऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए सभी पांच एंजाइमों के जीन को बैक्टीरिया में डालने की कोशिश कर रहे हैं।₹ सभी पांच एंजाइमों को बैक्टीरिया में डालने से क्षरण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, न केवल इसलिए कि एंजाइम क्रमिक रूप से कार्य करेंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि बैक्टीरिया में एकीकृत होने के बाद एंजाइमों का क्षरण कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। एक बार बैक्टीरिया में एकीकृत होने के बाद, एंजाइम लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं और बैक्टीरिया का उपयोग प्लास्टिसाइज़र को ख़राब करने के लिए लगातार किया जा सकता है। लेकिन जब एंजाइमों का उपयोग बैक्टीरिया में एकीकृत किए बिना किया जाता है, तो क्षरण प्रक्रिया को जारी रखने के लिए एंजाइमों के एक नए बैच का उत्पादन करने की आवश्यकता होती है। ₹हम बैक्टीरिया के अंदर गिरावट की प्रक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं।

डिजिटल दुनिया में गुम होते बच्चे

विजय गर्ग

हाल ही में आस्ट्रेलिया में सोलह वर्ष तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने के लिए विधेयक पास किया गया है। यह पहली बार है जब किसी देश में बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटाक जैसे सोशल मीडिया मंच इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर सोशल मीडिया कंपनियां ऐसा नहीं कर पाईं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद से विश्व के अनेक देशों सहित भारत में भी यह विषय चर्चा का बना हुआ है कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित होना चाहिए या नहीं। यह सच है कि आज की डिजिटल दुनिया में बच्चे छोटी आयु में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उसी में वे खोए रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में उनचालीस करोड़ अस्सी लाख युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं।

एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पाया गया कि नौ से सत्रह वर्ष की आयु के साठ फीसद बच्चे सोशल मीडिया या गेमिंग मंच पर प्रतिदिन तीन घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं। 'इंटरनेशनल जर्नल आफ पीडियाट्रिक रिसर्च' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 87.82 फीसद बच्चे सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे थे, जिनमें से वाट्सऐप 81.14 फीसद, फेसबुक 54.94 फीसद, ट्विटर 10.5 फीसद, यूट्यूब 70.61 फीसद, ईमेल 65.34 फीसद और नौ फीसद अन्य सोशल मीडिया माध्यमों का उपयोग कर रहे थे। यह एक तथ्य है कि सूचना क्रांति के बाद तेजी से उभरे डिजिटल युग ने समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से बच्चों और किशोरों के सामने एक गंभीर चुनौती उत्पन्न कर दी है। सवाल है कि क्या सोशल मीडिया को बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या वास्तव में इसे प्रतिबंधित किया भी जा सकता है या नहीं।

आनलाइन शापिंग, आनलाइन फूड डिलीवरी, आनलाइन चिकित्सीय सलाह, आनलाइन लेन-देन, आनलाइन पासपोर्ट आदि, यहां तक कि अब मंदिरों में दर्शन और प्रसाद भी आनलाइन संभव हो गया है। जब परिवार और समाज की हर आवश्यकता आनलाइन पूरी की जाने लगी हो, तो उस पर रोक लगाना कैसे संभव हो सकता है। क्या मनुष्य समाज से पुराने दौर कभी आधुनिक लौटना स्वीकार कर सकता है, क्या कभी मशीनों के स्थान पर अब फिर से बैलगाड़ी या हल से खेती करने को प्राथमिकता दी जा सकती है। संभवतः ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं हो सकता। इसलिए नई तकनीक को प्रतिबंधित करने के स्थान पर यह सोचना होगा कि इस चुनौतीपूर्ण परिवर्तन का सामना कैसे किया जा सकता है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग न केवल मानसिक स्वास्थ्य, बल्कि शारीरिक समस्याओं का भी कारण बन सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारियां बढ़ाने की मांग जोर पकड़ रही है। खासकर बच्चों की आनलाइन सुरक्षा पर कई देश नए कानून बनाने की कवायद कर रहे हैं। मगर जिस दौर में सब कुछ डिजिटल होता जा रहा

है, दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है, जहां विकसित तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में इसे प्रतिबंधित कैसे किया जा सकेगा। नव-उदारवादी व्यवस्था के उभार के बाद ही तो निगरानीमूलक समाज अस्तित्व में आया है, जहां हर कोई हर समय कैमरे की नजर में है। क्या आधुनिक तकनीक के बिना इस तरह की निगरानी रखना संभव हो सकता है? आए दिन 'डिजिटल अरेस्ट' और आर्थिक फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं क्या हम उनको रोक पा रहे हैं? जब साइबर अपराध जैसी घटनाओं को रोक नहीं पा रहे तो सोचा जा सकता है कि बच्चों को इनके उपयोग से कैसे रोका जाएगा। यह चिंता का विषय है।

कोरोना महामारी के बाद से तो जैसे शिक्षा का एकमात्र विकल्प 'स्मार्ट फोन' ही बन कर रह गया है। नई शिक्षा नीति में तो स्मार्ट फोन का उपयोग जरूरी सा हो गया है। आनलाइन सेमिनार सम्मेलन, कार्यशाला- प्रशिक्षण, लाइब्रेरी, ई-कक्षाएं वर्तमान शिक्षा पद्धति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गए र हैं। इसलिए सोशल मीडिया को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से वे ज्ञान और सूचना से भी दूर हो जाएंगे। यह जरूर है कि बच्चों को उसके सही उपयोग के लिए जागरूक किया जा सकता है। । स्मार्ट फोन में 'पैरेंटल कंट्रोल' या अभिभावकीय नियंत्रण की सुविधा के माध्यम से बच्चों के 'स्क्रीन टाइम' और गतिविधि पर नियंत्रण किया जा सकता है, उनके द्वारा देखे जाने वाली दृश्य सामग्री को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही यह यह भी पता लगाया जा सकता है कि बच्चे किस वेबसाइट या ऐप पर कितना समय बिता रहे या क्या देख रहे हैं। इसलिए बच्चों को सोशल मीडिया के लाभ और हानि के बारे में भी बताना जरूरी है। परिवार के साथ समय बिताएं, घूमने जाएं और घर से बाहर खेलने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी और फोटो साझा न करें, किसी अपरिचित से मित्रता आग्रह स्वीकार न करें। हानिकारक सामग्री को ब्लाक करें। बच्चों का 'स्क्रीन टाइम' सुनिश्चित करें। अधिकांश बच्चे 'आनलाइन गेमिंग के दौरान हैकरों को अपने यंत्र तक की पहुंच दे देते हैं, जिससे वे डिजिटल ठगी का शिकार हो सकते हैं। उन्हें सिखाना होगा कि किसी भी अपरिचित लिंक पर क्लिक न करें या ऐसे किसी भी ऐप को डाउनलोड न करें। आजकल बच्चे जहां भी जाते हैं, जो खाते हैं, पहनते हैं या खरीदते हैं, उसे सोशल मीडिया पर तुरंत अपलोड कर देते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए बच्चों को समझाना होगा कि वे अपना स्थान सोशल मीडिया पर साझा न करें। डिजिटल सुरक्षा के उपायों को जानें, समझें और आवश्यकता होने पर ही आनलाइन रहें मनोरंजन के लिए भौतिक संसाधनों का प्रयोग करें, दोस्तों के साथ समय बिताएं या खेलें, आभासी के बजाय वास्तविक संबंधों को समय दें। स्कूल के गृहकार्य या 'प्रोजेक्ट' के लिए गूगल या अन्य आनलाइन मंचों का उपयोग केवल सूचना प्राप्त करने के लिए करें। उस पर निर्भर न बनें।

बच्चों को आभासी समाज से वास्तविक समाज की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा। ऐसा करने में राज्य प्रशासन, समाज, परिवार, अकादमिक संस्थानों और नीति निर्माताओं सभी को अपनी भूमिका निभानी होगी, क्योंकि बच्चों को आभासी समाज की ओर धकेलने में कहीं न कहीं ये सभी जिम्मेदार हैं। मीडिया की भूमिका भी इस दिशा में कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मीडिया के पास लोगों, खासकर बच्चों को आकर्षित और प्रभावित करने की शक्ति होती है। वह बच्चों के व्यक्तित्व को सृजनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों ही तरह प्रभावित करता है। आज के दौर में मनुष्य को 'स्मार्ट' बनाने की जरूरत है जबकि मनुष्य मशीन को 'स्मार्ट' बनाने में लगा है।

बढ़ते मरुस्थल से घटते संसाधन

विजय गर्ग

पृथ्वी को मरुस्थलीकरण से बचाने और भोजन, कपड़ा आदि बुनियादी जरूरतों के लिए उत्पादक भूमि की रक्षा करना जरूरी है। विश्व की 3.20 अरब आबादी इस समय विस्थापन का संताप झेल रही है। स्थानीय स्थितियां लोगों को प्रवास के लिए विवश कर रही हैं। मिट्टी अपनी उत्पादकता खोती जा रही है। भू-प्रबंधन की व्यवस्था असुरक्षित हो रही है। भूमि-आधारित रोजगारों का समाधान ढूंढ़ पाना कठिन हो रहा है। तेजी से वनों की कटाई मरुस्थलों का विस्तार कर रही है। इस समय दुनिया में मात्र 60 फीसद जंगल बचे हैं। मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि पुनर्बहाली पर वैश्विक विमर्श हो रहे हैं। विश्व की 40 फीसद भूमि क्षरित हो चुकी है, यानी इसकी जैविक उत्पादकता लगातार ह्रास की ओर है। इसका जलवायु, जैव विविधता और लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। यह इसलिए भी चिंताजनक है कि भूमि क्षरण से सूखा, रेत और धूल भरे तूफानों से जन-जीवन दूभर हो रहा है। भू-वेत्ता और मौसम विज्ञानी आगाह कर रहे हैं कि आगामी दो दशक बाद दुनिया में भयावह सूखे के कारण तीन चौथाई आबादी को पेयजल संकट से दो-चार होना पड़ सकता है।

सूखे के साथ ही मरुस्थल बढ़ने के कारण वैश्विक मानचित्र तेजी से बदल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह, जलवायु परिवर्तन और खराब भूमि प्रबंधन है। सूखे के जोखिमों की प्रणालीगत प्रकृति दर्शाती है कि कैसे ऊर्जा, कृषि, नदी परिवहन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसी एक दूसरे से जुड़ी स्थितियां प्रभावित हो रही हैं। दुनिया भर में जन जीवन और आजीविका बचाने के लिए अब तो सूखे के प्रति सहन क्षमता बढ़ाने के लिए सत्तर से अधिक देशों का एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता - संचालित डेटा मंच भी सक्रिय हो चुका है। सूखा सहन सक्षमता साझेदारी को वित्तपोषित करने के लिए 2.15 अरब डालर के प्रारंभिक योगदान की घोषणा भी हो चुकी है।

तीन दशक पहले दुनिया के 196 देशों और यूरोपीय संघ ने मरुस्थलों से निपटने के लिए एक साझा मसविदे पर हस्ताक्षर किए थे। इसी पर आपसी विमर्श के लिए पिछले दिनों एक बैठक सऊदी अरब के रियाद में भी हुई थी। ताजा अध्ययनों से पता चलता है कि वर्ष 2000 के बाद से अब तक भूमि - क्षरण में 29 फीसद की बढ़ोतरी हो चुकी है। भूमि क्षरण से प्रभावित आबादी महंगाई, बेरोजगारी और अप्रत्याशित ऊर्जा बोझ से कराहने लगी है। भूमि और मिट्टी का नुकसान निर्धन परिवारों को पौष्टिक भोजन और बच्चों के सुरक्षित भविष्य से वंचित कर रहा है।

इस दिशा में सबसे सशक्त और सार्थक पहल संयुक्त राष्ट्र की रही है। भूमि बचाने में विश्व की

मौजूदा ढुलमुल आर्थिकी ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से धन जुटाने के प्रयासों को अब काफी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अनुमानित तौर पर इसके लिए संचयी निवेश वर्ष 2030 तक कुल 2.6 ट्रिलियन डालर जरूरी माना जा रहा है। नागरिक समाज संगठनों का कहना है, यह उतनी ही राशि है, जितनी दुनिया वर्ष 2023 में रक्षा बजट पर खर्च कर चुकी है। इस चुनौती से पार पाने के लिए अब सभी स्तरों पर निर्णय लेने में महिलाओं, युवाओं, चरवाहों और स्थानीय समुदायों की सार्थक भागीदारी को संस्थागत बनाना जरूरी हो गया है। हर साल दस करोड़ हेक्टेयर यानी मिस्र के आकार के बराबर की उत्पादक भूमि सूखा और मरुस्थल की भेंट चढ़ती जा रही है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया भर में बढ़ रहा सुखा ऐसा खामोश हत्यारा बन चुका है, जिससे बचना, ऐसे किसी भी प्रभावित देश के लिए असंभव सा होता जा रहा है। इससे कृषि, जल सुरक्षा और 1.80 अरब लोगों के लिए आजीविका का खतरा पैदा हो गया है। इसका सबसे बड़ा खमियाजा निर्धनतम देश भुगत रहे हैं। अंदेशा है कि निकट भविष्य में पानी जैसे आवश्यक संसाधनों की कमी लोगों के बीच बड़े टकरावों का कारण बन सकती है। विस्थापन का संकट और अधिक भयावह हो सकता है। बीते तीन वर्षों से दुनिया के ऐसे 30 से अधिक देशों में सूखे के भयावह हालात हैं। इस स्थिति से प्रभावित उरुग्वे, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया के साथ ही भारत, चीन, अमेरिका, कनाडा और स्पेन जैसे देशों पर भी इसकी छाया पड़ चुकी है।

सूखे के कारण यूरोप की राइन नदी का अनाज परिवहन और अमेरिका में पनामा व्यापार मार्ग बाधित हो चुका है। ब्राजील जलविद्युत संकट से जूझ रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि लगातार सूखा क्षेत्रों के विस्तार से वर्ष 2050 तक वैश्विक स्तर पर बड़ी संख्या में लोग सूखे की चपेट में आ सकते हैं। इसकी वजह वर्षा की कमी ही नहीं, जलवायु परिवर्तन और भूमि कुप्रबंधन भी है। पहाड़ी वनों की कटाई से व्यापक भू-क्षरण हो रहा है। इससे सूखा ही नहीं, ताप लहर और बाढ़ जैसे खतरे भी आसन्न हैं। ऐसी स्थितियों में आजीविका का जोखिम कई गुना बढ़ जाएगा। पारिस्थितिकी आपदा पूरे विश्व की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को झकझोर सकती है।

इस समय दुनिया भर में हरित मिशन चलाने वाले दस युवा 'भूमि ''भी' मरुस्थलीकरण पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें मुख्यतः मिट्टी क्षरण से एक हैं गरीब किसान परिवार के सिद्धेश सकोरे । वे की रोकथाम पर काम करने के साथ जैविक कृषि वानिकी नवाचारों से महाराष्ट्र के किसानों के लिए आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हैं। हरित उद्यमी रोकियातु त्राओरे माली में मारिंगा पेड़ पर आधारित एक सामाजिक उद्यम चला रही हैं। अब तक उन्होंने कई महिलाओं को 20 हजार मोरिंगा पेड़ों से जैविक चाय, पाउडर, तेल, साबुन, मसाले और शिशु आहार आदि बनाने में प्रशिक्षित किया है। जिम्बाब्वे के भूमि-नायक तकुदजवा एश्ले अपने संगठन 'फारेस्ट्री एंड सिट्रस रिसर्च' के माध्यम से मरुस्थलीकरण रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सैटेलाइट तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए दुनिया में सबसे संवेदनशील देश फिलीपींस में 'मसुंगी जियोरिजर्व फाउंडेशन' के अगुआ बिली क्रिस्टल जी डुमालियांग मनीला के आसपास लगभग 2,700 हेक्टेयर क्षतिग्रस्त जलग्रहण क्षेत्रों की पुनर्बहाली और पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने में जुटे हुए हैं। इसी तरह एस्ट्रिड पेराजा कोस्टारिका में जलवायु शिक्षक के रूप में एक बोर्ड गेम विकसित कर खिलाड़ियों को जलवायु परिवर्तन और उसके समाधानों का पाठ पढ़ा रहे हैं।

इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने प्राकृतिक स्थिरता और जन जीवन की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर की सरकारों, निजी क्षेत्र की आर्थिक शक्तियों और समुदायों से भूमि क्षरण की रोकथाम और पृथ्वी की रक्षा की दिशा में पुरजोर कदम उठाने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि हर सेकंड चार फुटबाल मैदानों के आकार की उत्पादक भूमि, क्षरण की चपेट में आ रही है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में घटते उत्पादन और बढ़ती खपत के गैर-टिकाऊ तौर-तरीकों के कारण भी प्राकृतिक संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे हालात में हर वर्ष विस्थापितों की संख्या बढ़ रही है।

आईटी कंपनी के शेयर धड़ाम, 46987 करोड़ रुपये घटा मार्केट कैप; किस वजह से आई गिरावट

परिवहन विशेष न्यूज

एचसीएल टेक ने सोमवार को दिसंबर तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे पेश किए थे। इसका कंसॉलिटेड नेट प्रॉफिट 5 .54 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 4591 करोड़ रुपये रहा। हालांकि इसके नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए। HCL टेक के शेयर करीब 10 फीसदी तक गिर गए। मोतीलाल ओसवाल रिसर्च का कहना है कि HCL टेक के तीसरी तिमाही के आंकड़े और चौथी तिमाही के लिए गाइडेंस निराशाजनक रहे।

नई दिल्ली। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी HCL टेक के शेयरों में मंगलवार को करीब 10 फीसदी की गिरावट आई। कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से कमजोर रहे, जिसके चलते निवेशकों में स्टॉक बेचने की होड़ लग गई। HCL टेक का शेयर बीएसई पर 9.41 फीसदी गिरकर 1,798.40 रुपये पर आ गया।

वहीं, एनएसई पर यह 9.63 फीसदी गिरकर 1,797.75 रुपये पर आ गया। बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी की सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा गिरावट HCL टेक में ही आई। इसकी बाजार हैसियत भी 46,987.11 करोड़ रुपये घटकर 4,91,743.25 करोड़ रुपये रह गई। HCL टेक के शेयरों में बाद में हल्की रिकवरी दिखी। यह दोपहर 12 बजे के करीब एनएसई पर 8.09 फीसदी गिरावट के साथ 1,828.45 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

HCL टेक पर ब्रोकरेज फर्मों की राय

घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल रिसर्च के अनुसार, ₹HCL टेक के तीसरी तिमाही के आंकड़े और चौथी तिमाही के लिए गाइडेंस निराशाजनक रहे।₹ HCL टेक के कमजोर प्रदर्शन का असर दूसरी आईटी कंपनियों पर दिखा। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसे अन्य आईटी स्टॉक भी गिरावट पर कारोबार कर रहे थे।

मिराए एसेट शेयरखान के कैपिटल मार्केट स्ट्रैटेजी के रिसर्च एनालिस्ट शाजी नायर ने कहा, ₹HCL टेक ने तिमाही आधार पर 3.8 फीसदी की अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। हालांकि, हमारा अनुमान था कि यह 4.8 फीसदी की ग्रोथ दर्ज करेगी, जहां तक पहुंचने में यह चूक गई।'

HCL टेक के नतीजे कैसे रहे

आईटी कंपनी एचसीएल टेक ने सोमवार को दिसंबर तिमाही के लिए वित्तीय नतीजे पेश किए। इसका कंसॉलिटेड नेट प्रॉफिट 5.54 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 4,591 करोड़ रुपये रहा। सीईओ ने मांग के माहौल और विवेकाधीन खर्च में सुधार की उम्मीद जताई और आने वाली तिमाहियों के ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाया। हालांकि, इससे निवेशकों का मनोबल नहीं बढ़ा और उन्होंने बिकवाली जारी रखी।

नोएडा मुख्यालय वाली आईटी फर्म ने एक साल पहले की अवधि में 4,350 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया था। कंपनी ने अपने ग्रोथ गाइडेंस के निचले सिरे को पहले के 3.5-5 फीसदी से बढ़ाकर 4.5-5 प्रतिशत कर दिया। समीक्षाधीन तिमाही में ऑपरेशन से रेवेन्यू 29,890 करोड़ रुपये रहा। इसकी तरह प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 3.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

थोक महंगाई ने दिया झटका, दिसंबर में आया बड़ा उछाल; पर अनाज का दाम घटने से मिली राहत

परिवहन विशेष न्यूज

थोक मुद्रास्फीति पिछले महीने यानी दिसंबर में बढ़कर 2 .37 प्रतिशत पर पहुंच गई। अनाज दाल और गेहूं की महंगाई में नरमी आई। हालांकि सब्जियों की मुद्रास्फीति दिसंबर में मामूली बढ़कर 28 .65 प्रतिशत रही। नवंबर में यह 28 .57 प्रतिशत थी। आलू की महंगाई 93 .20 प्रतिशत के उच्चस्तर पर बनी रही और प्याज की मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 16 .81 प्रतिशत हो गई।

नई दिल्ली। गैर-खाद्य वस्तुओं, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादों और ईंधन के दाम बढ़ने से थोक मुद्रास्फीति पिछले महीने यानी दिसंबर में बढ़कर 2.37 प्रतिशत पर पहुंच गई। हालांकि, इस दौरान खाद्य वस्तुओं की कीमतों में मामूली गिरावट आई। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति नवंबर, 2024 में 1.89 प्रतिशत थी। दिसंबर, 2023 में यह 0.86 प्रतिशत रही थी।

बता दें कि सोमवार को खुदरा मुद्रास्फीति के जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य कीमतों में कमी के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2024 में चार महीने के निचले स्तर 5.22 प्रतिशत पर आ गई।आंकड़ों के अनुसार, खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दिसंबर, 2024 में घटकर 8.47 प्रतिशत रह गई, जबकि नवंबर में यह 8.63 प्रतिशत थी।

अनाज, दाल और गेहूं की महंगाई में नरमी आई। हालांकि, सब्जियों की मुद्रास्फीति दिसंबर में मामूली बढ़कर 28.65 प्रतिशत रही। नवंबर में यह 28.57 प्रतिशत थी। आलू की महंगाई 93.20 प्रतिशत के उच्चस्तर पर बनी रही और प्याज की मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 16.81 प्रतिशत हो गई।

ईंधन और बिजली की मैन्युफैक्चरिंग दिसंबर में घटी

तिलहन जैसी गैर-खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति दिसंबर में बढ़कर 2.46 प्रतिशत हो गई, जबकि नवंबर में इसमें 0.98 की कमी आई थी। ईंधन और बिजली की बात करें तो दिसंबर में मुद्रास्फीति घटकर 3.79 प्रतिशत हो गई जबकि नवंबर में इसमें 5.83 प्रतिशत की कमी आई थी। मैन्युफैक्चरिंग वस्तुओं की मुद्रास्फीति 2.14 प्रतिशत रही, जबकि नवंबर में यह दो प्रतिशत थी।

घरेलू रेटिंग एजेंसी इक्रा के वरिष्ठ अर्थशास्त्री राहुल अग्रवाल ने कहा कि थोक मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण ईंधन, बिजली और प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी है। उन्होंने कहा कि थोक मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष में औसतन 2.5 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में तीन से 3.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

दिसंबर में पाम तेल आयात 41 प्रतिशत घटा

2024 के दौरान पाम तेल आयात में वार्षिक आधार पर 41 प्रतिशत की गिरावट रही है। उद्योग संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) के अनुसार, पाम तेल का मूल्य ढाई वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंचने के कारण सोयाबीन तेल की ज्यादा खरीदारी की गई है। एसईए के डाटा के अनुसार, पिछले महीने 5,00,175 टन पाम तेल का आयात किया गया है। वहीं, सोयाबीन तेल का आयात 3.2 प्रतिशत बढ़कर 4,20,651 टन रहा है।

हालांकि, सूरजमुखी तेल का आयात 22.3 प्रतिशत घटकर 2,64,836 टन रहा है। पाम और सूरजमुखी तेल की कम खरीदारी के कारण दिसंबर 2024 में देश का कुल वनस्पति तेल आयात 24.3 प्रतिशत घटकर 12.3 लाख टन रहा है, जो पिछले तीन महीनों में सबसे कम आयात है। कारोबारियों का कहना है कि स्टाक की कमी के कारण वैश्विक बाजार में पाम तेल का मूल्य बढ़ गया है।

चार महीने के निचले स्तर पर आई खुदरा महंगाई, क्या अब ब्याज दरों में कटौती करेगा आरबीआई?

परिवहन विशेष न्यूज

खुदरा महंगाई में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है। यह चार महीने के निचले स्तर पर आ गई है। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि आरबीआई जल्द ब्याज दरों में कटौती का तोहफा दे सकता है। दिसंबर 2024 में सब्जियों की महंगाई दर में थोड़ी नरमी आई है। हालांकि आलू मटर व फूलगोभी के दाम दिसंबर 2023 की तुलना में अब भी काफी अधिक है।

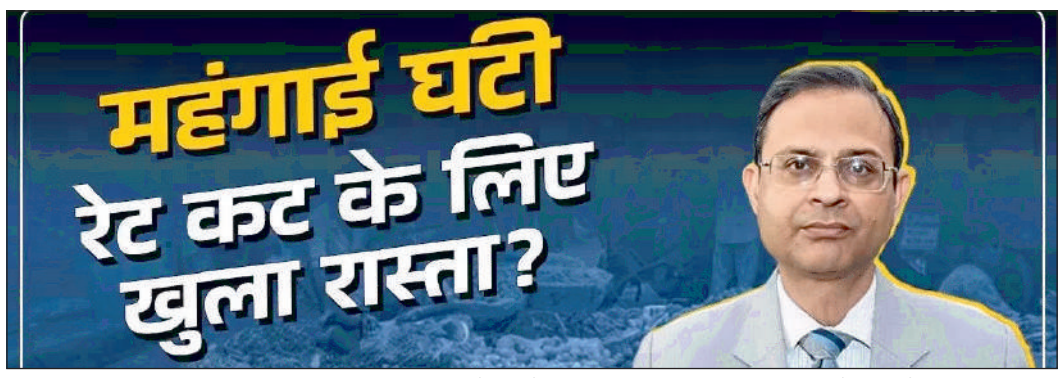

नई दिल्ली। आम जनता को लगातार दूसरे महीने महंगाई से राहत मिली है। खाने-पीने की चीजों का दाम घटने से दिसंबर में खुदरा महंगाई दर 5.22 फीसदी रही। यह खुदरा महंगाई का चार महीने का सबसे निचला स्तर है। दिसंबर 2024 में सब्जियों की महंगाई दर में थोड़ी नरमी आई है। हालांकि, आलू, मटर व फूलगोभी के दाम 2023 दिसंबर की तुलना में अब भी काफी अधिक है। नवंबर की खुदरा महंगाई दर 5.48 प्रतिशत थी।

क्या ब्याज दरों में कटौती करेगा RBI?

अगर खुदरा महंगाई दर में गिरावट का रुख जनवरी में भी जारी रहा, तो नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का रास्ता भी साफ हो सकता है। आरबीआई ने फरवरी 2023 से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर शक्तिकांत दास ने कई मौकों पर स्पष्ट किया था कि केंद्रीय बैंक का फोकस महंगाई घटाने पर है। केंद्रीय बैंक खुदरा महंगाई को 4 फीसदी तक लाना चाहता है।

हालांकि, अब नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुआई में आरबीआई ब्याज दरें घटाने पर विचार कर सकता है। इसकी वजह महंगाई का लगातार होना है। साथ ही, ब्याज दर घटाने से सुस्त होती इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई केंद्रीय मंत्री ब्याज दर घटाने की जरूरत बता चुके हैं। आरबीआई एमपीसी की अगली मीटिंग फरवरी 2025 में होगी।

दिसंबर 2024 में क्या सस्ता हुआ?

दिसंबर में सब्जी के खुदरा भाव में दिसंबर 2023 के मुकाबले 26.56 फीसदी की बढ़ोतरी रही। इनमें आलू, मटर, गोभी की सबसे अधिक भूमिका रही। आलू के दाम में दिसंबर 2023 के मुकाबले 68.23 प्रतिशत, मटर में 89.12 प्रतिशत, फूलगोभी में 39.42 प्रतिशत, लहसुन में 58.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।

वहीं, जीरा के दाम में 40 प्रतिशत, अदरक में 22 प्रतिशत तो सूखी मिर्च में 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। गत दिसंबर में सब्जी के अलावा खाद्य तेल व वनस्पति एवं फल के दाम में भी अच्छी बढ़ोतरी रही। खाद्य तेल में दिसंबर 2023 की तुलना में 14.60 प्रतिशत तो फल में 8.49 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

छत्तीसगढ़-बिहार में सबसे अधिक महंगाई

देश के अलग-अलग राज्यों में खुदरा महंगाई दर में काफी अंतर दिखता है। इसलिए वित्त मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि कि सभी राज्यों की महंगाई दर आसपास हो। मौजूदा रुख बताता है कि पिछड़े राज्यों में महंगाई दर अधिक होती हैं। वहीं, विकसित राज्यों में तुलनात्मक नजरिए से महंगाई काफी कम होती है।

इन्फलेशन डेटा बताता है कि गत दिसंबर में राष्ट्रीय खुदरा महंगाई दर 5.22 फीसदी रही। लेकिन दिल्ली में खुदरा महंगाई दर सिर्फ 2.51 फीसदी, तेलंगाना में 3.14 फीसदी, गुजरात में 4.93 फीसदी रही। वहीं, कम विकसित राज्यों की खुदरा महंगाई दर राष्ट्रीय दर की तुलना में काफी अधिक है। छत्तीसगढ़ में दिसंबर की खुदरा महंगाई दर 7.63 फीसदी, बिहार में 7.36 फीसदी, उड़ीसा में 6.96 फीसदी रही।

दिल्ली में महंगाई कम होने की वजह?

जानकारों का कहना है कि दिल्ली में महंगाई दर इसलिए भी सबसे कम है क्योंकि दिल्ली ट्रेडिंग सेंटर है और पूरे उत्तर भारत के लिए खाद्य वस्तुओं का भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। आसपास के सभी राज्यों के किसान अपना माल लेकर पहले दिल्ली आते हैं और फिर दिल्ली से देश के अन्य हिस्सों में माल की सप्लाई की जाती है। इसलिए दिल्ली में चीजें सस्ती होती है। दूसरा दिल्ली में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और अन्य ईंधन भी सस्ते हैं। महंगाई के डेटा में दिल्ली को इस बात का भी फायदा मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्र में विकास के अवसर क्या हैं, और निवेशक किस तरह से उठा सकते हैं फायदा

बेहतर कनेक्टिविटी उच्च शिक्षा तक पहुंच और कृषि पर कम निर्भरता ग्रामीण भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल रही है। देश की 64% आबादी गांवों में रहती है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 44% का योगदान देती है। यह असंतुलन धीरे-धीरे कम हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश अगले दो दशकों में भारत की विकास गाथा को आकार देगा और निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर भी प्रदान करेगा।

नई दिल्ली। भारत बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, और आर्थिक विकास की अगली लहर गांवों से शुरू होने वाली है, जिसे महात्मा गांधी ने भारत की आत्मा माना था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार के प्रभावशाली कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करेंगे और उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश अगले दो दशकों में भारत की विकास गाथा को आकार देगा और निवेशकों के लिए एक आकर्षक अवसर भी प्रदान करेगा।

ग्रोथ फाउंडेशन

देश की 64% आबादी गांवों में रहती है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 44% का योगदान देती है। यह असंतुलन धीरे-धीरे कम हो रहा है, जिसका श्रेय सरकार के ठोस प्रयासों को जाता है। इन प्रयासों में सन 2000 से अब तक 7.2 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.1 करोड़ घर बनाना, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण और 73% साक्षरता दर शामिल हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी, उच्च शिक्षा तक पहुंच, और कृषि पर कम निर्भरता ग्रामीण भारत के आर्थिक परिदृश्य को बदल रही है। ग्रामीण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (Gross Value Added - GVA) में कृषि का योगदान वित्त वर्ष 1994 में 56% से घटकर वित्त वर्ष 2022 में 40% हो गया है। वहीं, गैर-कृषि गतिविधियों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और कंस्ट्रक्शन का योगदान इसी अवधि में 44% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बदलाव कृषि से धीरे-धीरे दूरी का संकेत देता है, जो वर्तमान में 41.5% आबादी को रोजगार देने के बावजूद राष्ट्रीय GDP का केवल 16% हिस्सा है।

अगली लहर: मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर

ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक पुनरुत्थान के पीछे अवसरों की व्यापक श्रृंखला है। ट्रैक्टर और उपभोक्ता वस्तुओं जैसे पारंपरिक ग्रामीण-केंद्रित उद्योगों के विपरीत, यह लहर बैंकिंग, पैसेंजर कारों और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे क्षेत्रों तक फैल रही है। ग्रामीण भारत तेजी से आर्थिक विकास का इंजन बन रहा है और देश की विकास गाथा को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सरकारी कार्यक्रम सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। यह बदलाव भारत के लिए नए अवसर खोलता है, खासकर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां प्रमुख सेक्टर्स की पहुंच अभी भी सीमित है।

निवेश का अवसर

ग्रामीण विकास के अवसर का लाभ उठाने वाले इच्छुक निवेशक ICICI Prudential Rural Opportunities Fund पर विचार कर सकते हैं। यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम उन सेक्टर्स और कंपनियों में निवेश करती है, जो ग्रामीण भारत के विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। न्यू फंड ऑफर (NFO) 9 जनवरी से 23 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध है।

ग्रामीण क्षेत्र में संभावनाओं को पहचानें: निवेशकों के लिए विकास का अवसर क्या है?

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रामीण भारत में ग्रोथ की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य किफायती आवास देना है। जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ नल जल कनेक्शन स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बदलती तस्वीर निवेशकों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि सीधे निवेश करने के बजाय पेशेवर फंड मैनेजरों के माध्यम से निवेश करना अधिक उपयुक्त हो सकता है।

नई दिल्ली। भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी), जिसका उद्देश्य किफायती आवास प्रदान करना है। इस योजना के तहत अब तक 2.1 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है, जिससे निर्माण क्षेत्र और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिला है।

इसी तरह, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 11 करोड़ नल जल कनेक्शन स्थापित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। इन परियोजनाओं ने जल प्रबंधन और स्वच्छता उत्पाद निर्माण से संबंधित कंपनियों को लाभ पहुंचाया है।

इन योजनाओं का प्रभाव न केवल ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में दिखता है, बल्कि महिलाओं को पानी लाने में लगने वाले समय की बचत और स्वास्थ्य सुधार के माध्यम से भी महसूस किया गया है। बचा हुआ समय और बेहतर स्वास्थ्य ग्रामीण आबादी को अधिक उत्पादक बनाने और नए अवसरों का लाभ उठाने में सहायक हो सकता है।

सरकारी योजनाओं ने आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण अभियान ने ऊर्जा की खपत में वृद्धि की है और बिजली से चलने वाले उपकरणों और सौर ऊर्जा उत्पादों की मांग को बढ़ाया है। इसके साथ ही, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी पहलों ने भारतीय विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इनसे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं।

इसके अलावा, PLI (Production Linked Incentive) स्कीम के तहत सरकार ने कंपनियों को निवेश और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस योजना ने प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने परिचालन स्थापित करने के लिए आकर्षित किया है।

ग्रामीण क्षेत्रों की बदलती तस्वीर निवेशकों को इस विकास यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि, सीधे निवेश करने के बजाय पेशेवर फंड मैनेजरों के माध्यम से निवेश करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। पेशेवर मैनेजर जटिलताओं को समझने, जोखिमों का सही आकलन करने और निवेश पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करने में विशेषज्ञता रखते हैं, जिससे बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ICICI Prudential Rural Opportunities Fund एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। यह फंड मुख्य रूप से उन क्षेत्रों और कंपनियों पर केंद्रित है जो ग्रामीण भारत के विकास और वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं। ICICI Prudential Mutual Fund द्वारा लॉन्च की गई यह ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम 9 जनवरी, 2025 से 23 जनवरी, 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध है।

बजट में सीमा शुल्क स्लैब को 40 से घटाकर पांच करने का सुझाव, जानें क्या होगा इसका असर

नई दिल्ली। आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने सोमवार को कहा कि आगामी बजट में सरकार को सीमा शुल्क स्लैब को 40 से घटाकर पांच करके शुल्क संरचना आसान बनाना चाहिए। साथ ही यह सुनश्चित करना चाहिए के आयात बिलों में कटौती, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को बढ़ाने के लिए कच्चे माल पर कम कर लगाया जाए। जीटीआरआई ने एक रिपोर्ट में भारत के सीमा शुल्क ढांचे को परिष्कृत करने, अंतरराष्ट्रीय जांच से बचने और शुल्क को राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप रखने के लिए शुल्क नीतियों की अंतर-मंत्रालयी समीक्षा की मांग की।

जीटीआरआई ने देश के औसत सीमा शुल्क को लगभग 10 प्रतिशत तक कम करने का सुझाव देते हुए कहा कि इस मकसद को किसी बड़े राजस्व नुकसान के बगैर भी हासिल किया जा सकता है। फिलहाल 85 प्रतिशत शुल्क राजस्व केवल 10 प्रतिशत आयात शुल्क श्रेणियों से आता है, जबकि 60 प्रतिशत शुल्क श्रेणियों का राजस्व में तीन प्रतिशत से भी कम अंशदान है।

सीमा शुल्क से कितनी होती है कमाई?

रिपोर्ट के मुताबिक, सीमा शुल्क की भारत के सकल कर राजस्व में हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 6.4 प्रतिशत रह गई है जबकि कारपोरेट कर (26.8 प्रतिशत), आयकर (29.7 प्रतिशत) और जीएसटी (27.8 प्रतिशत) इससे काफी आगे हैं। रिपोर्ट कहती है, 'सीमा शुल्क के स्लैब को 40 से घटाकर पांच पर लाना, अधिकतम शुल्क को 50 प्रतिशत पर सीमित करना और यह सुनिश्चित करना कि कच्चे माल पर तैयार माल की तुलना में कम कर लगाया जाए, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगा, आयात निर्भरता को कम करेगा और निर्यात बढ़ाने में मदद करेगा।'

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ सकती है टैरिफ वॉर

इस बीच वैश्विक स्तर पर टैरिफ वॉर गहराने की आशंका है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इसे लेकर कनाडा भी जवाबी टैरिफ की तैयारी कर रहा है। इस बीच, कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रविवार को कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बारे में ट्रंप की टिप्पणी ने अमेरिकी उपभोक्ताओं को भारी टैरिफ से होने वाले नुकसान से ध्यान भटका दिया है।

आखिर प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा का कारण क्या है?

आंकड़ों के अनुसार, जो लोग आजीविका की तलाश में स्थानीय और क्षेत्रीय सीमाओं के पार जाते हैं, उन्हें अपने मेजबान समाज में स्थायी रूप से बाहरी समझे जाने का अपमान सहना पड़ता है। श्रमिकों को अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर दुखद घटनाओं के पात्र के रूप में दिखाया जाता है, जिससे उनके योगदान और उन्हें प्राप्त मान्यता के बीच का अंतर उजागर होता है। राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के पीछे की ताकत होने के बावजूद, राष्ट्रीय महानता के विमर्श में उनकी भूमिका को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है। पॉलिसी शून्य होने के कारण अक्सर असुरक्षित छोड़ दिया जाता है यद्यपि प्रवासी कार्यबल राष्ट्रीय गौरव के प्रत्यक्ष चिह्नों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, फिर भी उनके अधिकारों को नियंत्रित करने वाली नीतियों का घोर अभाव है।

--डॉ सत्यवान सौरभ

भारत के असंगठित कार्यबल का एक महत्त्वपूर्ण लेकिन कमज़ोर वर्ग, प्रवासी श्रमिक, अक्सर सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से बाहर रह जाते हैं। दशकों से कानूनी ढाँचे और सिफारिशों के बावजूद, सामाजिक सुरक्षा तक उनकी पहुँच अपर्याप्त रही है। अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 में प्रावधान और असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग (2007) और असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (2008) द्वारा श्रमिक पंजीकरण के लिए सिफारिशों के बावजूद, ई-श्रम पोर्टल तक प्रवासी श्रमिक आधिकारिक डेटाबेस में काफ़ी हद तक अदृश्य रहे। जबकि ई-श्रम पोर्टल पर 300 मिलियन से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, उनमें से अधिकांश को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में एकीकृत नहीं किया गया है। मौसमी और परिपत्र प्रवासियों को वंचितता, कलंक, तस्करी और सार्वजनिक सेवाओं तक खराब पहुँच सहित अनूठी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी उच्च गतिशीलता सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को जटिल बनाती है। कई श्रमिकों में डिजिटल साक्षरता या ई-श्रम पंजीकरण और लाभ ट्रैकिंग के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुँच की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। राज्यों में अक्सर कल्याणकारी योजनाओं का असंगत कार्यान्वयन होता है, जिससे समन्वय सम्बंधी समस्याएँ पैदा होती हैं जो लाभों की पोर्टेबिलिटी को कमज़ोर करती हैं।

मौजूदा कल्याणकारी योजनाएँ जैसे कि मनरेगा, पीएम श्रम योगी मानधन और वन नेशन वन राशन कार्ड अक्सर अलग-अलग तरीके से काम करती हैं, जिससे प्रवासी श्रमिकों के लिए निर्बाध पहुँच में बाधाएँ पैदा होती हैं। 2021 में लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों का दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। इसमें 300 मिलियन से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें प्रवासियों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात शामिल है। यह कल्याणकारी योजनाओं के लिए श्रमिकों की बेहतर पहचान और लक्ष्यीकरण की सुविधा प्रदान करता है। हालाँकि, यह मुख्य रूप से एक रूपंजीकरण अभियानरू है जिसका सामाजिक सुरक्षा में समावेश पर सीमित ध्यान है। 2024 में लॉन्च किया गया विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत करके पंजीकरण और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। इसके लाभों में एकीकृत दृष्टिकोण, लाभों की पोर्टेबिलिटी और पारदर्शी तथा श्रमिक-अनुकूल प्रक्रिया शामिल है। हालाँकि, चिंताओं में मौजूदा योजनाओं का सीमित कवरेज, श्रमिकों में जागरूकता की कमी और अंतर-राज्य समन्वय का कमज़ोर होना शामिल है। ई-श्रम पोर्टल और ओएसएस प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली सामाजिक सुरक्षा चुनौतियों को सम्बोधित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण क़दम है। हालाँकि, उनकी सफलता कार्यान्वयन बाधाओं पर काबू पाने, निर्बाध अंतर-राज्य समन्वय सुनिश्चित करने और श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने पर निर्भर करती है।

आंकड़ों के अनुसार, जो लोग आजीविका की तलाश में स्थानीय और क्षेत्रीय सीमाओं के पार जाते हैं, उन्हें अपने मेजबान समाज में स्थायी रूप से बाहरी समझे जाने का अपमान सहना पड़ता है। श्रमिकों को अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर दुखद घटनाओं के पात्र के रूप में दिखाया जाता है, जिससे उनके योगदान और उन्हें प्राप्त मान्यता के बीच का अंतर उजागर होता है। राष्ट्र के बुनियादी ढांचे के पीछे की ताकत होने के बावजूद, राष्ट्रीय महानता के विमर्श में उनकी भूमिका को शायद ही कभी स्वीकार किया जाता है। पॉलिसी शून्य होने के कारण अक्सर असुरक्षित छोड़ दिया जाता है यद्यपि प्रवासी कार्यबल राष्ट्रीय गौरव के प्रत्यक्ष चिह्नों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, फिर भी उनके अधिकारों को नियंत्रित करने वाली नीतियों का घोर अभाव है।

अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979, इस विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करने वाला एकमात्र कानून है।

हालाँकि, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, न्यूनतम मजदूरी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं की रोकथाम के लिए इसके प्रावधान अक्सर अधूरे रह जाते हैं।

प्रवासी श्रमिकों के साथ उनकी मानवता पर विचार किए बिना एक नौकरी मशीन की तरह व्यवहार किया जाता है। सरकारी प्रणालियाँ अक्सर प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों और परिवर्तनों की परवाह नहीं करतीं।

प्रवासी श्रमिकों को न केवल कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती बल्कि उन्हें शहर के प्रतिकूल वातावरण में भी संघर्ष करना पड़ता है। शहर सड़कों और इमारतों जैसे निर्माण के लिए प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन इन शहरों में इन प्रवासी श्रमिकों की बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त सहायता नहीं होती है। यहां स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सहायता, रहने के लिए अच्छे स्थान, सुरक्षा उपाय या बच्चों की देखभाल की सुविधाएं नहीं हैं। इससे प्रवासी श्रमिकों को सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की दुर्दशा विशेष रूप से चिंताजनक है। शिशुओं को बड़े बच्चों की देखभाल में छोड़ दिया जाता है, जिनके पास स्वयं सार्थक शैक्षिक गतिविधियों तक पहुंच नहीं होती। इससे असुविधा का एक चक्र निर्मित होता है, जहां शिक्षा के अवसरों की कमी उनके माता-पिता द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों से मुक्त होने की उनकी क्षमता में बाधा डालती है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए, एक टूटा हुआ अंग अक्सर कामकाजी जीवन के अंत का संकेत देता है। कार्यस्थल पर लगी चोटों के लिए शायद ही कभी पर्याप्त सहायता या चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हो पाती हैं। घायल श्रमिक अपने घर लौटने के लिए बाध्य होते हैं, तथा उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक त्वरित और आवश्यक पहुंच बहुत कम उपलब्ध होती है। गांवों से शहरी क्षेत्रों की ओर मौसमी प्रवास की आवश्यकता, प्रवासी श्रमिकों के समक्ष चुनौतियों को और बढ़ा देती है। शहरी आवास की स्थिति अक्सर बहुत खराब होती है, जिससे शहर का मौसम दुख का एक अतिरिक्त स्रोत बन जाता है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए काम से परे जीवन की गंभीर वास्तविकताएं तत्काल ध्यान देने और व्यापक समाधान की मांग करती हैं। विचारशील शहरी नियोजन को कार्यस्थलों से आगे बढ़कर प्रवासी श्रमिकों के जीवन के संपूर्ण आयाम को शामिल करना चाहिए, जिससे न केवल रोजगार बल्कि सम्मान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध हो सके। बच्चों के लिए शिक्षा के अवसरों की उपेक्षा, घायल श्रमिकों के लिए सहायता की कमी, तथा शहरी आवास की प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिकों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है। उनकी विविधता का केवल जश्न मनाने के बजाय, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए एक ही नीति के दृष्टिकोण से हटकर सूक्ष्म नीतियों की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, जो प्रवासी श्रम शक्ति की जटिलताओं पर विचार करें।

थल सेना दिवस

सेना दिवस के अवसर पर पूरा देश थल सेना की वीरता अदम्य साहस और शौर्य की कुर्बानी की दास्ताँ को बयान करता है। जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली में सेना मुख्यालय के साथ-साथ देश के कोने-कोने में शक्ति प्रदर्शन के साथ-साथ भारतीय सेना की मुख्य उपलब्धियों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सेना दिवस, भारत में हर वर्ष 15 जनवरी को लेफ्टिनेंट जनरल (बाद में फ़ील्ड मार्शल) के. एम. करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय के भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर से यह पदभार ग्रहण किया था। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी ना कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिये अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया।

इतिहास 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश भर में व्याप्त दंगे-फसादों तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल-पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। इसके पश्चात एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया, ताकि विभाजन के दौरान शांति-व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। परन्तु भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। उनसे पहले यह पद कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। के एम करिअप्पा पहले ऐसे अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी। उन्होंने साल 1947 में भारत-पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया था।

'रूसी सेना में शामिल भारतीयों को रिहा करो', युद्ध में केरल के युवक की मौत के बाद भड़का विदेश मंत्रालय

युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे एक भारतीय की मौत हो गई है। वहीं एक अन्य घायल हो गए हैं । मृतक की पहचान केरल के त्रिचूर जिले के निवासी बिनिल के रूप में हुई है। इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बताया कि हम मृतक व्यक्ति के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं।

नई दिल्ली। अगस्त, 2024 में राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के साथ हुई मुलाकात में पीएम नरेन्द्र मोदी ने रूस की सेना में भारतीयों को गलत तरीके से भर्ती किये जाने का मुद्दा सीधे तौर पर उठाया था।

तब पुतिन के निर्देश के बाद रूस ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि सेना में जितने भी भारतीय हैं, उन सभी को वापस भेजा जाएगा। लेकिन हाल ही में रूस की सेना की तरफ से बताया गया है कि एक भारतीय की मौत हो गई है। वह व्यक्ति केरल का नागरिक है। जबकि केरल का ही एक दूसरा नागरिक युद्ध में घायल है जिसका इलाज चल रहा है।

युद्ध के लिए भारतीयों को लुभा रहा रूस

भारत ने इस मुद्दे को फिर से रूसी पक्ष के साथ सख्ती के साथ उठाया है। बताया जा रहा है कि भारत की आपत्ति के बाद तब रूस की सेना के लिए भर्ती करने वाली एजेंसियों ने कुछ समय के लिए भारतीय युवाओं को निशाना बनाना बंद कर दिया था लेकिन अब जब यह मामला शांत हो गया है तो उनकी तरफ से फिर से दुबई व खाड़ी के दूसरे शहरों के जरिए भारतीयों को लुभाने का काम शुरू हो गया है।

भारत सरकार ने जताई मौत पर चिंता

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बताया कि हमें रूस की सेना में भर्ती किये गये केरल के एक नागरिक की मौत होने की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की खबर का पता चला है। भारत का एक और नागरिक जो केरल का है, घायल हुआ है और उसका इलाज वहां के अस्पतालों में चल रहा है। हम मृतक व्यक्ति के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करते हैं।

मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास मृतक व्यक्ति के साथ संपर्क में है और हरसंभव मदद करने की कोशिश कर रहा है।

रंधीर जायसवाल ने आगे बताया,रमृत भारतीय के शरीर को जल्द से जल्द स्वदेश लाने की कोशिश हो रही है। घायल भारतीय को शीघ्रता से वहां से छोड़े जाने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही नई दिल्ली में रूसी दूतावास के साथ उठाया गया है। हमने अपनी यह मांग फिर से सामने रखी है कि जो भी भारतीय वहां की सेना में हैं, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाना चाहिए।"

रूस ने क्या दी है दलील?

भारत ने पिछले साल जब यह मुद्दा उठाया था तब रूस के नई दिल्ली स्थित दूतावास ने कहा था कि रूसी सेना को भारतीयों की जरूरत नहीं है। जो भारतीय वहां गये हैं वह अपनी मर्जी से असैनिक कार्यों के लिए ठेके पर गये हैं। जबकि रूस की सेना से जिन भारतीयों को यहां लगाया गया उनमें से कई ने बताया था कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि उनकी तैनाती युद्ध भूमि में होगी और वहां युद्ध में हिस्सा लेना होगा।

कई भारतीयों ने भाषा की समझ नहीं होने और रूस-यूक्रेन युद्ध में सीधे भेजे जाने की बात भी कही थी। यह मुद्दा भारत ने रूस के समक्ष उठाया था। प्राप्त सूचना के मुताबिक केरल के त्रिशुर के रहने वाले बिनिल बाबू की मौत युद्ध भूमि में हुई है जबकि इसी शहर के जैन कुरियन गंभीर तौर पर घायल हुए हैं।

कुरियन ने मॉस्को स्थित एक अस्पताल में भर्ती होने के बाद अपने परिजनों से संपर्क किया जिसके बाद पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है।

पारादीप में पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में मिले स्पेयर पार्ट्स

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर: डुप्लीकेट रोलिंग पार्ट्स चीन से आ रहे हैं। पारादीप दोचकी स्थित जेके इंजीनियरिंग में भारी मात्रा में बुलडोजर के नकली पार्ट्स जब्त किए गए। इन्हें जेके इंजीनियरिंग शोरूम में स्टॉक कर बेचा गया। दिल्ली में CAT कंपनी के फील्ड ऑफिसर को इसकी खबर मिली तो कलकत्ता और दिल्ली के दो डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहां छापेमारी की गई और सारी जानकारी सामने आ गई।तीनों वितरक चीन से डुप्लिकेट पार्ट्स बेचते पाए गए। CAT कंपनी के असली पार्ट्स की कीमत 8 से 10 हजार होती है, जबकि चीन से आने वाले नकली पार्ट्स महज 700 से 1 हजार रुपये में बिकते थे। पारादीप एडिशनल एसपी के नेतृत्व में लॉक स्टेशन और पारादीप एडम्स पुलिस स्टेशन पर छापेमारी की गई और डुप्लीकेट पार्ट्स को जब्त कर लिया गया और मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि, जेइंजीनियर के मालिक ने स्पष्ट किया है कि सामान वापस नहीं किया जा सकता है गलती से चीन से भेज दिए गए थे। दूसरी ओर, पारादीप पुलिस ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

बासुकिनाथ मंदिर से राजस्थान के जस्टिस की मोबाइल चोरी ,बरामद

झारखंड के बिहार, बंगाल व बांग्लादेश सीमा से चार अपराधी गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड-झारखंड

रांची। झारखंड के दुमका जिला स्थित प्रसिद्ध शैव्य पीठ बासुकिनाथ धाम में वर्ष के पहले दिन पूजा के लिए आए राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश का मोबाइल चोरी होने के मामले में जरमुंडी पुलिस ने अंतरराज्यीय मोबाइल चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया।चोरों से मुख्य न्यायाधीश का मोबाइल फोन समेत कुल आठ चोरी मोबाइल फोन बरामद हुए ।

जरमुंडी थाना ने मामले हाई प्रोफाइल से जूडे रहने के कारण उसकी गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश जांच टीम के साथ तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर साहिबगंज जिले के तीनपहाड़ इलाके के एक मोबाइल चोर गिरोह की संलिप्तता पाई।

इसके बाद, तीनपहाड़ के बाबूपुर गांव से दो चोरों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश सीमा से अन्य अपराधियों को पकड़ा गया।गिरफ्तार सभी अपराधियों को रविवार को न्यायिक प्रक्रिया के तहत दुमका केंद्रीय जेल भेज दिया गया ।

'इमरजेंसी' की रिलीज से तीन पहले कंगना को झटका, यहां नहीं दिखाई जाएगी फिल्म; जानिए वजह

फिल्म इमरजेंसी की रिलीज से पहले कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों ने बताया रिलीज से पहले बांग्लादेश में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। कंगना की फिल्म अब बांग्लादेश में नहीं रिलीज की जाएगी। भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों से के कारण ये फैसला लिया गया है। कंगना की ये फिल्म रिलीज होने से पहले भी सुर्खियों में रही है।

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' इस समय काफी चर्चा के केंद्र में है। पहले फिल्म की रिलीज डेट को कई बार बदला गया। तमाम चर्चाओं के बाद ये फिल्म अब 17 जनवरी से सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी। इस बीच कंगना रनौत को बड़ा झटका लगा है।

दरअसल, बांग्लादेश में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। फिल्म इमरजेंसी बांग्लादेश में नहीं रिलीज की जाएगी। अन्य स्थानों पर इस फिल्म को इस शुक्रवार रिलीज किया जाना है। पिछले कुछ समय में भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण रिश्ते देखने को मिले हैं। कंगना रनौत की फल्मि 'इमरजेंसी' 1975 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी द्वारा भारत में घोषित आपातकाल पर आधारित है।

बांग्लादेश में नहीं रिलीज होगी फिल्म

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, रबांग्लादेश में 'इमरजेंसी' की स्क्रीनिंग रोकने का फैसला भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों से जुड़ा है। प्रतिबंध फिल्म की विषय-वस्तु से कम और दोनों देशों के बीच चल रही राजनीतिक गतिशीलता से अधिक जुड़ा है।"

इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस दौरान अमेरिका ने भले ही उनसे दोनों देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने की मांग की थी। इसके बाद भी इंदिरा गांधी आगे बढ़ीं। ऐसा माना जाता रहा है कि उन्हें लगा कि लाखों शरणार्थियों को शरण देने के बजाय, भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध करना आर्थिक रूप से बेहतर होगा, जिसके परिणामस्वरूप 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ।

शेख मुजीबुर रहमान की हत्या का भी जिक्र

कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सेना और इंदिरा गांधी की सरकार की भूमिका और शेख मुजीबुर रहमान को दिए गए से समर्थन पर भी प्रकाश डाला गया है। शेख मुजीबुर को ही बांग्लादेश का जनक कहा जाता रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी को देवी दुर्गा कहा था।

कंगना की फिल्म में बांग्लादेशी चरमपंथियों के हाथों शेख मुजीबुर रहमान की हत्या को भी दिखाया गया है। जिसके कारण माना जाता है कि बांग्लादेश में फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के खिलाफ दो मोर्चों पर युद्ध लड़ा था, जो बाद में बांग्लादेश बन गया।

वर्तमान युग में, बांग्लादेश उपमहाद्वीप में भारत का एकमात्र सहयोगी था। हालांकि, बांग्लादेश से शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के साथ भारत के समीकरण बदल गए है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023